

THE DEPUTY CHAIRMAN:  
We will tell him. Don't worry. We  
will give him enough time.

SHRI ASHOK MITRA (West  
Bengal): You kindly tell us.

THE DEPUTY CHAIRMAN :  
First you and then the Minister.  
Okay? Agreed? Happy? (Interrup-  
tions) The Government business is  
our business. It is our responsibility  
the House has to pass it.

Now, Mathursahab.

I. STATUTORY RESOLUTION  
SEEKING DISAPPROVAL OF  
THE CABLE TELEVISION  
NETWORKS (REGULATION)  
ORDINANCE, 1994 PROMUL-  
GATED ON THE 29th SEPT.,  
1994.

II. THE CABLE TELEVISION  
NETWORKS (REGULATION)  
BILL, 1993.

उपसभापति : माथुर साहब, मेरी एक  
विनती है कि जितना टाइम पार्टी को दिया  
गया है, कृपया उसी टाइम में आप बोलें।  
कोई ज्यादा बोलेगा तो आई विल डिसकन्टिन्यू  
दि डिसकशन।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) :  
महोदया, मेरा निवेदन यह है कि जो डिस-  
अप्रूवल का मोशन मूव करता है वह इस टाइम  
में नहीं आता। वह अलग समय है। मैं संक्षेप में  
कहूंगा।

उपसभापति : आपका उसमें नहीं है।  
आपकी बी.जे.पी. की तरफ से डिस-अप्रूवल  
हो रहा है और यह डिस-अप्रूवल का समय  
इसमें नहीं है। वह अलग है आप अपना  
भाषण शुरू करें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : 23 मिनट में  
से उनका समय पार्टी के समय में

शामिल न किया जाये। वह अलग है।  
मंत्री जी जो समय लेंगे वह पार्टी के समय में  
शामिल नहीं होता। वह अलग है। मेरा  
समय मत लीजिए।

उपसभापति : आप जब बोलना शुरू करेंगे,  
उस टाइम से आपका समय नोट होगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपसभापति  
महोदया, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा ताकि  
मेरे दूसरी साथी मलकानी जी भी कुछ  
कह सकें।

सबसे पहले मैं इस बात पर खेद प्रकट  
करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने आर्डिनेंस  
जारी करने के लिए ज सफाई दी है वह  
सर्वदा अनकन्विसिंग है, उससे कोई बात पूरी  
नहीं होती।

उन्होंने कहा है कि चूँकि बहुत से अप्रेंटिज  
को दबाया जा रहा था, कोहिंस किया जा  
रहा था, स्थिति वास्तव में इससे उल्टी  
हुई है। मेरे पास दास्तावेज मौजूद हैं  
इसमें दो बड़ी कंपनियों ने दिल्ली में  
स्वयं दबाव डाले हैं। एक ए०ए०एस०  
आई०ए० जो कि इंडिस्ट्रियल, टेक्नोलोजी  
प्राइवेट लिमिटेड हिन्दूजाज की है, मेरे हाथ  
में यह कांटेक्ट है, जिन्होंने यहाँ पर दबाव  
डाल कर लोगों को खरीदना चाहा। ऐसे  
ही दूसरी कंपनी है जी०टी०वी०, उन  
लोगों ने भी किया है। एक बिलकुल शायद  
मंत्री महोदय के सामने कैसे भी आया  
होगा पश्चिम बिहार में उन्होंने वाकायदा  
जी०टी०वी० का कंट्रोल रुम स्थापित किया।  
आप कहें तो नाम भी ले दूँ। कोई हरी  
गोयनका हैं उनके माध्यम से दबाव डाल  
कर पैसे के लेन देन की बात की है।  
ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं। इसलिए  
यह कहना कि वास्तव में इसलिए किया  
गया था कि बड़े लोग दबाव डाल कर न  
खरीद सकें, इसका उल्टा हो रहा है।  
यह कम्पनीज विदेशी कम्पनीज जैसी ही  
हैं। इसलिए इस बात को रोकना चाहिये।  
दूसरी व्यावहारिक कठिनाई क्या है। आपने  
उस दिन कहा कि इसके एलज वने हैं और  
इस्ट्रक्शंस गये हैं। मेरे पास जानकारी है कि

यहां पर दिल्ली में कम से कम किसी भी डाकखाने में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। उनके पास फार्म उपलब्ध नहीं है। डाकखाने में जाते हैं तो उनकी मना कर देते हैं और यह कहते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। स्थिति यह है। इसलिए आपका यह दावा कि आपने विशेष उद्देश्य के लिए ऑर्डिनंस जारी किया, वह बिल्कुल स्थापित नहीं होता। इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र इस विषय में कार्यवाही करने की कृपा करें।

दूसरा जो मुझे सब में ऑब्जेक्शनेबल लगता है, आपने कहा है कि विदेशी प्रभाव तो रोका जाए। इसमें उल्टा हो रहा है। जो बिल के सेक्शंस हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकषित करना चाहता हूं। सेक्शन एक में—

‘person’ ‘person’ means what?

“(i) an individual who is a citizen of India;”

ठीक है। तम्रर दो—

“(ii) an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not,.....”

“(iii) a company in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the citizens of India;”

बात ठीक है लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई बैठा है और उसने एजेंट्स यहां हैं वह कंपनी को नहीं चला सकते? इसके साथ ही आपने दरवाजा खोल दिया है। अब आइये सेक्शन 17 में, आप जो सजा देने वाले हैं ऑफिस में, उसमें आप यह कहते हैं—

“Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was

committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”

जो विदेशी कंपनी के शेयर्स हैं, उसका आदमी कहीं बाहर बैठा है, उसकी इंस्ट्रक्शंस मौखिक है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। गलत है। इसमें आग—

“(a) ‘company’ means any body corporate and includes a firm or other association of individuals;”

बात ठीक है लेकिन यहां पाकिस्तान के एजेंट बहुत हैं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि आई०एस०आई० का जोर है। इसके अन्दर यह भी हो सकता है कि यहां पर कंपनी बनाई जाएगी जो चाहे वह प्रोपेगंडा करती रहे। इसीलिए आपने मिसलेनियस में सेक्शन 20 में कहा है—

“Power to prohibit operation of cable television network in public interest.”

अगर आप चाहे किसी कंपनी को लार्जली रोक नहीं सकते हैं। आपने कहीं यह प्रोविजन किया है जिसकी आप चाहे वह कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड न हो। Can you do it?

कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। सब से बड़ा जो खतरा है, वह यह है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने यह किया है, इस उद्देश्य को यह बिल पूरा नहीं कर सकता है। इसमें बहुत मं खतरे हैं। जहां छोटे छोटे आप्रटज को समाप्त कर दिया जाएगा, वहां विदेशी प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। यद्यपि आपने किया नहीं है जिसकी कहते हैं नीचे किसी को अधिकार देना, फ्रीवाइज करना, फ्रीवाइज तो हो जाएगा। अगर दबाव डाला गया कि आप केवल टी०वी० से 100 रुपये लेते हैं, आप हमको 15-रुपये दोगुने बाकी पैसा आप रख सकते हैं। और हमारे नाम से इस्तेमाल करिए।

तो सबसे बड़ी चीज तो मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि किन्हीं बड़ी-बड़ी कम्पनियों को, विदेशी हों या स्वदेशी, सारे हिंदुस्तान पर छाने का अवसर नहीं देना चाहिए वरना जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए "जी" टी०वी० है या और टी०वी० है, उन्होंने सारा खरीद लिया तो एक तो यह मोनोपोली होती है, नम्बर दो, पोलिटिकली वे सारे राजनीति को प्रभावित कर सकेंगे। कल अगर एक कम्पनी है जो हिंदुस्तान में—बम्बई में, दिल्ली में—सब तरफ अपना नेटवर्क बढ़ा लेती है और कोई भी पार्टी उसे खरीद ले, ही कैन परवेस डट, तो वह पार्टी आपकी राजनीति को, आपकी आर्थिक व्यवस्था को डायरेक्ट करने की स्थिति में होगी। इसके विषय में आपने अभी तक जिसको कहते हैं कोई क्वायट या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं चाहूंगा कि इसके विषय में आप बाकायदा कुछ चिन्ता करें। इस विषय में और कहूंगा। बड़ा खुला सवाल है। आज साइंस बहुत बढ़ गयी है। आप जानते हैं कि थोड़े दिनों में ऐसी स्थिति आ जाएगी जबकि टी०वी०, रेडियो, टेलीफोन, ये सब एक लाइन पर आ जाएंगे—फाइबर जिसको कहते हैं, नया बनने के बाद। आपने कहा तो दिया है कि किसी प्रकार से जो रेडियो है या दूसरे आपके साधन हैं उसमें वह इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका उल्टा सांचा। क्या आपने किसी प्रकार की व्यवस्था की है कि बड़े टेलीकम्युनिकेशंस—आप विदेशी टेलीकम्युनिकेशन कम्पनियों को बुला रहे हैं—उसको टेकओवर न करें। आपने क्या व्यवस्था की है? बड़े-बड़े समाचार पत्र हैं—टाइम्स आफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी हों, कल वे कहेंगे हमको यह अधिकार है, हम न्यूज पेपर चलाने हैं, हम जो आपरेटर्स हैं इनको ले लेंगे। जब तक आप इन पर बंधन नहीं लगा सकते हैं तब तक कोई भी आज जो छोटे आपरेटर्स हैं वे समाप्त हो जाएंगे। उनमें से एक मोनोपोली पैदा हो जाएगी जिसके कारण से राजनीति और बाकी नीतियों को, चाहे वह कोई पोलिटिकल पार्टी हो, सरकार को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए

मैं चाहूंगा कि इस चीज को सरकार को क्लियर करना चाहिए। आपने एक और टी०वी० के लिए तो कर लिया है जिस १ पेड-चैनल कहते हैं। आपके पास व्यवस्था है। मैंने सुना है। मंत्री जो बना सकते हैं कि स्कैम्बलर जिसको कहते हैं वह व्यवस्था की है। आप क्या समझते हैं कि आज जो टेली आपरेटर्स हैं, ही कैन डू इट? उसके पास आज इतना पैसा नहीं है। सामान्यतः छोटे कंट्रोल रूम जो बनाने में दस से बारह लाख रुपये की आवश्यकता होती है। एक अच्छा मिडिल क्लास का आदमी कर सकता है। मेरा निवेदन यह है—शायद दिल्ली में, मैं श्योर नहीं हूँ, हुआ हो या केन्द्र में हुआ हो, इसको में स्माल स्केल इंडस्ट्री माना गया था, और नहीं माना गया है तो ये जो केवल आपरेटर्स हैं इतनी स्माल स्केल इंडस्ट्री में मानें जिससे कि बड़े-बड़े पैसों वाले प्रभावी लोग और सरकार एक मोनोपोली स्थापित न कर सकें। यह मेरा आपने निवेदन है।

दूसरी बात, साफ्टवेयर पर आता हूँ। आज चैनल्स शायद 40-50 होंगे। आपका ही कहीं वस्तव्य है शायद 70-80 तक करने वाले है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है तो और देशों में डेढ़-डेढ़, दो-दो, तीन-तीन हजार चैनल्स... (व्यवधान) हाँ, हाँ, मैडम इतने है। अगर चैनल्स बढ़ गए तो आप उनका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। क्या आपने व्यवस्था की है?

उपसभापति : सौ-दो सौ तो सुना है, दो तीन हजार का तो नहीं सुना है।

श्री जगदीश प्रसाद मायुर : नहीं, नहीं। दो सौ तो अपने यहां ही हो जाएंगे।

उपसभापति : आप जीरो ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर. एक कम्पनी नहीं, डिफरेंट कम्पनीज मिला करके। दूसरा, जो नयी व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं, क्या उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है। मैं उदाहरण देता हूं। चैनल तीन आपका है। बड़ी परेशानी हुई है आपको। आज तक उसका मेटलमेंट नहीं हुआ है...

SHRI MISA R. GANESAN  
(Tamil Nadu): The translation is not coming, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN:  
In English?

SHRI MISA R. GANESAN : Yes

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह मेरा समय न काटिए।

उपसभापति : नहीं, नहीं।  
If you are not being heard by Members, what is the point in your making the speech? Let him be heard.

SHRI MISA R. GANESAN: It is coming now, Madam.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लिहाजा, ये प्रोपोजीशंस जैसे मैंने पेड चैनल आदि कहा, इनकी भी आप चिंता करें। दूसरा, आज फिल्म हैं। फिल्में आती हैं। कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स का और जो ये कैसेट्स बनाते हैं उनका तो कुछ समझौता है प्रापस में लेकिन यह गरीब जो आपरेटर हैं यह क्या करेगा। तो आपको लीगली कोई न कोई इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि मैं देखना चाहता हूं नयी फिल्म तो सिनेमा हाल में जाऊं, कम से कम 25, 26 या 30 रुपये खर्च करूं। वह भी शायद करने को तैयार हैं। लेकिन आप कैसेट्स जो बनाते हैं, उनको परमिशन है तो आप उनको परमिशन देंगे या नहीं देंगे या कहेंगे आपस में समझौता करने की स्थिति आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए फिर आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी आवश्यक होगी। खैर एक तो आपने

अच्छा किया है कि दूरदर्शन की आपने पहले मांग की थी कि दो वह उनके प्रोग्राम दिखाएं, आपने एक कर दिया। यह तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें न्यूज शामिल हैं? क्या नेशनल न्यूज इसमें शामिल हैं या नहीं? यदि एक ही है तो केवल नेशनल न्यूज दिखा दें, बाकी खत्म। लिहाजा आपको दो बातें चाहिए। एक, जब चैनलज बढ़ने वाले हैं तो आप साफ्टवेयर भी इतना तैयार कर सकते हैं आज टैलीविजन पर साफ्टवेयर की इतनी कमी है। पुरानी-पुरानी रद्दी सड़ी पिक्चर्स दिखा देते हैं। अब चैनलज बढ़ जायेंगे अगले दो, चार, दस साल में तो आप क्या करेंगे? इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। तीसरी आपकी जिम्मेदारी है, जिसको ट्रांसनेशनल न्यूज कहते हैं, एक विदेशी से कोई आया है किसी नेटवर्क ने दिखाया तो उसको आप दिखा दीजिए। आपने जिम्मेदारी इसमें डाली है कि जो आपरेटर हैं उसकी जिम्मेदारी होगी। हाउइज ही रेसपांसिबल अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं स्क्रेवलिंग की जैसे कहते हैं आप करिए और मैं कहूंगा हिन्दुस्तान की सरकार इसमें सक्षम है। मैं पूरी तरह से और दावे से नहीं कह सकता, शायद कुछ देशों में जानकारी है। उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। कोई सेन्दल उनका अरेंजमेंट है कि वे कैन पुट इट ऑफ। जब चाहे उसको निकाल देंगे कैन यू डू इट? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरा मेरा एक सुझाव है, आप जो केबल आपरेटर्स हैं उनके एरियाज बांट दीजिए, जिससे कि कोई भी बड़ी कंपनी आकर छा न सके। आपने बांटा कि इस एरिया में इतने लोक करेंगे, इस एरिया में इतने लोग करेंगे, लेकिन बड़े शहरों में अथवा छोटे शहरों में भी एरियाज बांटे हम लोग जब विचार करते हैं तो बात करते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की, लेकिन छोटे जो गांव हैं, मान लीजिए एक छोटा कस्बा या डिस्ट्रिक्ट है, वदायूं का मान लीजिए और आप चाहते

है जहाँ केवल टी०वी० लगा दिया तो कोई भी आदमी वहाँ के गांवों में जा सकते हैं कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपने खुला छोड़ दिया है कि जो चाहे लगा दे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ जाएँ। आप कुछ न कुछ बड़े शहर वम्बई, कलकत्ता को छोड़ कर भी इसकी व्यवस्था और दिखाने दें।

आपने एक और बात कही है। एडवर्टाइजमेंट का कोड, कौन सा कोड, उस दिन मेने अर्ज की थी कि कोड कौन सा है। आपने कहा कि जो पुराना कोड, पिछली सदी का। क्या आपने इस बिल में कहीं कहा है कि फ्ला-फ्ला कोड लागू होगा। यू हैव नाट मैड एनीथिंग। ऐसे ही जो स्टैंडर्ड आपने कहा कि इन्विजमेंट होना चाहिए, ठीक बात है। आपने स्टैंडर्ड कह दी है कि इतने-इतने साल भर के पीरियड के अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। साल भर तो खत्म होने वाला है, आपने क्यों नहीं किया है? यू हैव नाट उन इट। फिर आपने जो इन्विजमेंट्स है, पूछना चाहंगा बाहर से जो जाना है उसमें फ्री की ड्यूटी है। आप क्या करना चाहते हैं, उसको क्लैरीफाई तो करिए। अब इसमें नहीं कहा है। तो कहंगा कि आप बोलते समय कहिए कि हमकी स्थिति क्या बनाना चाहते हैं। रूलज, आपने कहा रूलज बने उस दिन तमाशा हो गया। रूलज यहाँ बनेगे या डाकखाने वाले बना रहे हैं। डाकखाने में बना रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, इन एक तमाशे की स्थिति है और मैं पूछना चाहंगा कि आर्डिनेंस या आज इस के बीच में, कौन से रूल में काम हो रहा है। अगर यू वर्किंग इन ए वैक्यूम? क्या कर रहे हैं? फिर दूसरा रूलज आपने कहा है कि इस बिल में कि वह सदन के सामने रखे जायेंगे। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि सदन के सामने पूरी चीज जानी चाहिए। रूलज भी आएँ, आपका जो कोड है वह भी आए। मैं चाहंगा कि इस पर आप क्लेरिफिकेशन दें।

अंत में एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। जो आपने वंड की बात कही है, ठीक है। आपने कहा है कि उसको 90 दिन के अंदर नोटिस दिया जाना चाहिए। 90 दिन बहुत होते हैं। अगर किसी का आपने इन्विजमेंट कैंप्चर किया है, और कौन करेगा, एक छोटा आफिसर, आपने ऊपर के एक सीनियर मोस्ट आफिसर को कुछ कह दिया है जो कि सर्टिफाइ या अथोराइज होगा स्टेट गवर्नमेंट में, अब उसका डिसेंजन है कि वह कौन सा समझता है कि उचित या अनुचित है, बंद कर देगा, और आपने उसको कह दिया कि 90 दिन में नोटिस देना। तीन महीने में, वह तो एक दिन देखकर तय कर देता है, "नो इट इज रांग।" यह आपने प्रोहिबिट कर दिया और आप कहते हैं कि 90 दिन में होगा यानी 90 दिन तो उस बचारे का कारोबार बंद हो गया। उसका कारोबार बंद न हो और वह उसे चलाता रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि why can't you do it in 15 days? अगर वह केवल आधा घंटा, पौन घंटा या दस मिनट कार्यक्रम को देखकर तय कर सकता है कि यह अनुचित है, भद्दा है, खराब है, गंदा है तो अब उसको प्रूव करने में तीन महीने लगेंगे और तीन महीने तक वह आदमी लटका रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो केवल आपरेटर्स हैं—इन्हें रमाल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में स्वीकार किया जाए। दूसरे आज उनका काम-धंधा बंद न हो और यह थड़े-बड़े पैसे वालों और कंपनियों के हाथ में न जाए, विदेशी आक्रमण से इसका बचाव हो, इसका आप ध्यान रखें। इतना ही कहकर मैं इन बातों पर आपसे स्पष्टीकरण चाहंगा। जहाँ तक बिल की आत्मा का सवाल है, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन जो उसमें खामियाँ हैं, उन्हें दूर करने का आप प्रयत्न करें। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN:  
Shri Vayalar Ravi. The Hon. Mem-  
ber is absent.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Madam, our friend, Mr. Jethmalani has some urgent business to go. If you agree, I will request hon. Members to let him speak now and go.

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Madam, there was some misunderstanding. I had thought that I was the first to speak at 2.30. Therefore, I fixed up a meeting. If I speak now, I don't think there will be any objection.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House does not have objection, I think he can speak and go. But please confine yourself to the stipulated time. आप अपने समय के अंदर बोलिएगा।

श्री रामजेट मलानी : मैं समय बाँरो कर लूंगा।

उपसभापति : यहां बाँरोयिंग नहीं चलता।

This is a House.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: But he can steal it.

SHRI RAM JETHMALANI: I hope the hon. Minister and the Government will take my criticism in the spirit in which I want to say it. It is meant to be a constructive criticism. It is meant to help the Government to administer this law; it is meant to prevent the Government from having unnecessary litigations which will only bring it to some amount of embarrassment.

First of all, you had declared the purposes in the Statement when the Ordinance was brought into force. You have mentioned four purposes. The first is that there is a mushrooming of cable television networks. I do not find in the whole Bill single provision which enables you to control the mushrooming of these cable net-

work operators because the only qualification for registration is prescribed in Clause 2E. Under Clause 2E, if a person is a person within the meaning of the Act, he has the right to be registered. So, how are you going to control this mushrooming business? The Bill does not indicate at all.

The second purpose, which is perhaps the legitimate purpose to some extent, is this. You have said that you want to protect the small operators. If that is the purpose, you won the support and admiration of my hon. friend, Mathur sahib, but I find that in the Bill you have no power, you have no such provision. How do you propose to control big operators from taking over? I do not know. There is no power, once again. Once again you go back to Clause 2E. Under Clause 2E whoever is the person, as defined, will have the right to operate one of these television units.

The other purposes, which you have given, are all obnoxious to the Constitution. You must realise and the Government should realise, and I want hon. Members of the House to appreciate, that this is a seemingly innocuous measure. But, in substance, it raises great issues of Constitutional importance. You are dealing first with the rights of free speech of those who want to appear on the television networks and express their opinions on moral issues, on social issues, on political issues, on aesthetic issues and even on commercial issues. And, second, which is still more important, is the correlative and concomitant right of the people to know. The people are entitled to know the truth and the people are entitled to the fullest possible information. Once you are dealing with these two important rights of somebody to express his ideas and all others to receive those ideas, these rights

become the foundation of constitutional democracy. Unless you have a completely informed electorate, there can be no democracy. The second principle which is involved which is equally a very, very important principle is that ultimately the right of free speech and the right to form our own conclusion is a part of human dignity, is a part of human intellectual and spiritual autonomy because these are the issues which are involved. Sir, the third important issue which the Bill seems to forget totally is that the democracy is based upon the philosophy of the great philosopher, Voltaire when he said, "I don't accept a word of what you say. But I shall give my life to defend your right to say." Now, in other words, nobody has the right to prescribe good test. Nobody has the right to prescribe the nature of views which are acceptable to the society. I may not accept the views on good taste and the so-called vulgarity and obscenity of either your Government or the bureaucrats who help you. Therefore the Bill does not take notice of these great Constitutional principles at all. In fact, truth has a very uncanny habit of leaking out. You have said that you want some kind of censorship. Censorship is repugnant to our Constitution. Those who have committed offences, those who are doing something which is prohibited by law, for them laws have already been made. Laws to control free speech have already been made. They are all laws which impose reasonable restriction in the right of free speech. The law of libel, the law of defamation, the law of contempt of court, the law relating to not spreading communal and religious violence are there. All these laws have already been brought to existence under article 19(2) of the Constitution. They have already restricted the right of free speech and the right to receive a speech from others. Now, you cannot

go beyond that. The cat is out of the bag when you say that the provisions of this Bill are supposed to be in addition to the various kinds of laws, the list of which you have already given in clause 21. Now, you have no right at all under the law to restrict the free speech beyond the parameters of article 19(2) of the Constitution. The whole of article 19(2) of the Constitution has already been exhausted by the existing laws and you cannot impose any further restrictions upon the right of free speech.

[Vice Chairman (Shri Suresh Pachouri) in the Chair.]

Sir, the fundamental principle of democracy is that if there is some kind of untruth, that untruth will be faced with truth in the free market of ideas and the truth will collide with error and ultimately the truth has to succeed on its own independent merit in a free competition of ideas. The Government has no right to say what the truth is. The Government has no right to say what is good for the people. You are not treating the people of this country as school children for whom you are going to act as some kind of parent and prescribe what they want to hear. What is the kind of culture they want to imbibe? You have said that foreign culture is coming in. But I might like some elements of foreign culture. I like, for example, elements of a culture in which the politicians are not corrupt. I like elements of a culture in which the people speak the truth all the time and not the kind of falsehood which goes on in this country. Therefore, you cannot say that your culture is superior and going to impose it on others by calling it as an Indian culture which adds insult to the injury. First of all, you impose a false culture on us, then, you tell us that you are imposing the Indian culture. Now

this is a kind of tyranny which I will not tolerate and this Bill seems to be based on that philosophy.

Sir, unfortunately, I have very little time to devote and I want to point out to you what this Bill does. Under clause 5 everybody is to conform to the code. Under clause 6, everybody is supposed to conform to the advertisement code. Now, what is the programme code? The programme code is not laid down in the Bill. Yesterday, I am sorry to say the Minister was misguided by his bureaucrats or perhaps it was his own error. He told us that this was the same old thing which was operating and we will find it in the Library and the Library happened to be closed on Saturday. At least he had the good sense to send out a copy of the rules to us. Now these two codes are contained in the Bill, the statutory rules which have been framed. Now look at this. For breach of clause 5 and clause 6, whoever contravenes these rules will be punished, for criminal offence. Under clause 16 also, whoever contravenes any provisions of this Bill shall be punished and the rules in the so-called code have this provision. Your rule says, for example you shall not do anything which is against good taste. In other words, you have now created a criminal offence punishable with one year's imprisonment, which says that whoever hereafter does not act in good taste shall be punished with imprisonment which may extend to two years. This is the kind of offences you are creating under the rules. Please look into the rules. I appeal to you. All your rules, except one or two, are outside the ambit of Article 19(2) of the Constitution. The first rule of creating offence is that you must create those offence in such clear language that he who runs it may read it. After all, when you are

saying to people, "Don't do this," they must know what exactly you are asking them not to do. How can you have an offence in which you say that a person shall not speak half-truth and you will decide whether the person has spoken half-truth? And the law says that whoever shall speak what the Government thinks is half-truth, shall be punished with imprisonment! I do not want to use strong language. But this is one of the most absurd provisions that I have come across. Sit down and modify the programme code as well as the advertisement code. Bring it in conformity with the Constitution; make it specific; and use more precise and better language. The English are gone, but still we use the English language. It is a horrible language in your rules. I have no time to point out each one of the rules, how there are grammatical and other mistakes.

Sir, as I said, this is a seemingly innocuous measure, but is, really, a wolf in sheep's clothing. If you allow this kind of invasion of liberties to take place, you will have taken the first step in the direction of destruction of the liberty of free speech and our Constitutional values. I oppose it because your two legitimate purposes are not carried into the Act and your remaining purposes are totally obnoxious to the Constitution. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN : (Shri Suresh Pachouri) : Shri John F. Fernandes. Absent, Shri Vayalar Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala)  
 Mr. Vice-Chairman, Sir, I support this Bill because it is a major measure in the field of our electronic media. (Interruptions). In this, the Minister has taken a step to control, regulate and prevent, to an extent, the infiltration by other forces which may

have an encroachment on the cherished values of our cultural inheritance.

When the cable TV operations started becoming very large in the country, a profitable business, the Bill was introduced in 1993 whereby some restrictions and regulations were sought to be made. An opportunity was given for the big business to intervene and purchase the small groups started in different cities. I happened to read a report in the "Business World" recently. Many major groups are coming into the field with foreign collaborations. They want to spend enormous amounts—the RPG group, Rs. 1,000 crores and the Hindujas, Rs. 500 crores—to control the electronic media. This is a very important factor. In the Objectives of the Ordinance, the Minister has said in the third paragraph that this measure is to prevent the large way entry of the big business and also to protect the interests of the small operators. I agree with it and I want him to stand by that.

The second objective is this. The cultural invasion into the day-to-day activities of our social life by the foreign media makes a negative impact on the society. Before making two or three other points, I want to make one point clear. The Bill itself says in one or two clauses that the main intention is to prevent such a kind of cultural invasion. In this country, today, the new generation is being influenced by the electronic media where many types of satellites are transmitting different cultural activities to this land because the sky is free now. So, our new generation is being influenced to that extent and that influence is not as good as we expect it to be. That influence is not good for the Indian society and the Indian traditions. We have our own traditions. Instead of circulating our own traditions to the outside world, we are proceeding

in a different way which is not good for the society. That is one part of it. You rightly said that to prevent the cultural invasion the debate is whether we should allow the foreign media to print on this soil or not. If the intention of the Bill is to make rules and regulations to prevent any kind of cultural invasion or the invasion of our cultural inheritance, it is all right. But the attempt of the foreign media, which has its own publication to print, is itself a problem. Here, the Indian print media project our national interests and our views to the world and the foreign media project their views to this nation for the consumption of the Indian nation. This is the basic difference. Here, the media does the service. It is part of our nation; it is part of the society, it is part of the politics and it is part of the establishment. The print media represent the national interests. Today, some people are debating this and the debate itself is unwanted and should not be allowed in this country. If the foreign media are allowed to print in this country, it would mean that we are allowing our nation and the people to know what foreign people want to convey to the Indian people. It is not in the interest of our nation. It is not in the interest of the Indian society. But it is to their interest. They want to sell their idea to this country. So, any attempt to allow the foreign media to print in this country will go against our national interests. So, I wonder what will happen tomorrow if somebody from Pakistan or somebody from our neighbourhood wants to have print media which can print for them from India. Anybody can have it. I do not want to name anybody. Our national interests are there. Our system is an open system. Ours is a democracy. It is one of the biggest democracies in the world. We have the freedom of press. The Constitution of India guarantees the free-

dom of press. The Indian Constitution is one of the best Constitutions in the world and one of the democratic institutions that we have, is our Parliamentary system. This system exists in the Indian Constitution which guarantees the fundamental rights, that is, the freedom of expression. But, here the basic question is, is it the freedom of expression of the Indian citizens or is it the question of freedom of expression of foreign citizens? The foreign media owned by foreign citizens cannot claim the freedom of expression meant for the Indian citizens and you cannot allow the foreign media to print and claim that freedom. I believe, it will be a bad time even to discuss this issue and allow the foreign media to come to this country. I would oppose this. I know, Mr. J. Shah, is very happy because the rules are being circulated. He demanded them and they have been circulated. But those rules must be strictly enforced. But which is the enforcing authority? Will you leave this aspect completely to the post offices or will you have a separate authority? The Minister may consider this point. The Bill contains certain clauses which can be discussed and interpreted because the Government wants to fix certain criteria for control to prevent certain kind of propagation. If you allow the State Government officers to do it, I think it is not a proper assessment of the situation and I wish that the power to control and enforce this law need not be delegated to the State Government. It can be done through your own agency. It can be either a registered agency or something like that. Whatever it be, it should be your own institution.

Then comes the punishment, for which I moved an amendment. You give them punishment. You

say, the punishment is six months imprisonment, or there is a minimum imprisonment of two years. Okay. Then what is the fine? A thousand rupees. There is no relationship between the fine and the term of imprisonment in criminal laws. There is no relationship between a fine of a thousand rupees and an imprisonment of two years. The fine is Rs. 1,000/-. How can the imprisonment be two years? I am for imprisonment of five years or ten years; I do not mind, but there should be some relationship between the two in your recommendation. When this House passes a law, it should not be a laughing stock before the judiciary or the lawyers. I can understand the logic of fixing it today as one thousand rupees. But there must be some relationship between the two. That is why I moved the amendments for a minimum fine of five thousand rupees and for reducing the punishment, making it first six months and then increasing it to two years. I do not mind if you want two years of imprisonment, but then definitely the fine must be increased. You have to fix a minimum of ten thousand rupees; otherwise, there is no relationship between the fine of ten thousands rupees and the imprisonment of two years. And for the second offence, you said, it can be extended to seven years or something like that and there is a fine of five thousand rupees. Therefore, Sir, I suggest that when the punishment is fixed, there must be a relationship between the fine and the imprisonment. That is why I moved the amendments. While I am fully supporting this enactment, my only request is, the objectives of the Bill or the Ordinance should be fulfilled (1) to protect the interests of small cable operators and (2) to prevent the invasion of our cultural inheritance and the cornering of the small groups by the monopoly houses which are spending crores of rupees in collaboration with foreign groups;

whether it is RPG Group or Hinduja Group. And by spending thousands of crores of rupees, there is also an attempt by such groups to control the public opinion and also influence the poor people in the society. Such vested interests are also showing up again in the name of liberalisation. So, I wish, the Minister will be able to implement the provisions of the Bill strictly.

Thank you, Sir.

**श्रीमती जयलक्ष्मी (पश्चिमी बंगाल) :** धन्यवाद माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। एक अमूर्त, अर्थव्यय, अवास्तविक और अनुपयोगी विदेशी को अर्थव्यय के जरिए लागू किया जाना अपने आप में एक हंसी की बात है और उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हंसी मूर्त हुई है, हमारे इस केवल नेटवर्क रेगुलेशन अध्यादेश के जरिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने विश्व को देखें तो हम पाते हैं कि एक ओर तो साम्राज्यवाद अपने आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को क्षत-विक्षत कर रहा है और एक ऐसे समय में यदि हमें कोई दफती की तलवार भांजता हुआ दिखाई दे तो ऐसी स्थिति पर या तो सिर्फ हंसी या कड़वी है या सिर्फ रुलाई ही आ सकती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसे रण-बांकुरों के उद्देश्यों पर तो हम संदेह नहीं कर सकते लेकिन ऐसे रण-बांकुरों की हार या जीत पहले से ही सुनिश्चित होती है और उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय जो अध्यादेश लेकर आए हैं, उस अध्यादेश की हार और जीत पहले से ही, मैं यह कहना चाहूंगी कि सुनिश्चित हो चुकी है। खुद हमारे मंत्री महोदय कितने बड़े भ्रम में हैं। उस अध्यादेश की अतिवार्थिता पर उन्होंने जो अपना बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि विदेशी उपग्रहों से प्राप्त होने वाले सिग्नलों के जरिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर घातक प्रहार हो

रहे थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विदेशी संस्कृति के उप-घातक प्रहारों से बचाने के लिए यह अध्यादेश उन्हें लाना पड़ा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हालांकि मंत्री महोदय का उद्देश्य तो नेक है, लेकिन हमारे मंत्री महोदय खुद अपने ही उद्देश्य को किस तरह भूल जाते हैं, यह हमें तब पता लगता है, जब हम उनके इस अध्यादेश को देखते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश की धारा 5 और 6 में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि विदेशी उपग्रहों से प्राप्त होने वाले कार्यक्रमों पर अध्यादेश की पाचवीं और छठी क्लॉड संशोधन धारा, विकल्प संबंधी धारा नहीं होगी। यानी कि जिस खतरे को रोकने के लिए हम उपाय कर रहे थे, उसी खतरे को खुद ही छुट दे दी गयी है।

इसका अर्थ है, इरादा था, लड़ने के लिए तलवार खींचकर डाल दिये हैं। तो यह है, इस अध्यादेश का उद्देश्य। उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मैं पूरे सदन के साथ प्रस्ताव को लेकर इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि जब हम यह बात करते हैं कि विदेशी उपग्रहों से हिन्दुस्तान की संस्कृति को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो हमारे इस आज के माहौल को देखें, खासकर पिछले तीन-साढ़े तीन वर्षों से देश में अध-उदारतावाद की जो आंधी बहाई जा रही है, उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अध-उदारतावाद किमलिए? यह अध-उदारतावाद किसी कट्टर साम्प्रदायिक विचारों के विश्व नहीं है, यह उदारतावाद पश्चिम और साम्राज्यवादी विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए है। तो इस उदारतावाद की आंखों में हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अपनी छोटी सी हैसियत में यह अध्यादेश लेकर आए हैं कि वह सारी अप-संस्कृति का मुकाबला कर लेंगे। इसीलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि वह जो छोटी सी हैसियत में यह अध्यादेश लाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ दफती की तलवार भांजने जैसी या डॉन क्विक्जोटिक एक्सरसाइज के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं लगता। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विस्फोट या उनका संघान हमारे देश के लिए सभी

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

चीज है और यह भी सच है कि हमारे देश के नीति-निर्धारकों ने शुरु से ही इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रति अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण को रखा था और इसके लिए कई कमेटियाँ बनायी गयीं और उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी कि किस तरह भारत के लिए, भारत की अपनी वस्तुगत स्थितियों में इन माध्यमों का हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तमाम परिस्थितियों की परिणति के रूप में हिन्दुस्तान का वैकल्पिक दृष्टिकोण इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के संबंध में प्रसार भारती के संबंध में आया था। तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रति हमारा जो वैकल्पिक दृष्टिकोण होना चाहिए था, वही वैकल्पिक दृष्टिकोण हमारे इस केबल नेटवर्क रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं, केबल नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिये भी हमारे सामने वही परिप्रेक्ष्य होना चाहिये था, वही दृष्टिकोण होना चाहिये था कि किस तरह अपने राष्ट्रीय मान मूल्यों को दृष्टि में रखते हुये, राष्ट्रीय मान मूल्यों को नजर में रख हुये हमारा यह केबल नेटवर्क काम कर सके। वैसे वैकल्पिक दृष्टिकोण हमारे सामने होना चाहिये था लेकिन उप सभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मंत्री महोदय जो नख-दंतहीन अध्यादेश लेकर आये हैं, वह अध्यादेश अपने पूरे के पूरे उद्देश्यों में नाकाम रहेगा। उप सभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अध्यादेश में कहा है कि इसके 90 दिनों के अन्दर ही केबल आपरेटर्स को खद को पंजीकृत करवाना होगा और 31 दिसम्बर को 90 दिन खत्म हो जायेंगे पर अब एक हालत यह है कि इन केबल नेटवर्क को रेगुलेट कौन करेगा, इनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, किसी को मालूम नहीं है। केबल आपरेटर्स इधर-उधर दौड़ रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो लेकिन उन्हें कहा जाता है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

तो काम करने का हमारा तरीका यह है। हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि केबल आपरेटर को एक सेंसर अधिकारी की भूमिका अदा करनी होगी। वह सेंसर अधिकारी केबल चलाकर बैठ जायेगा और केबल से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम को देखेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो हम उदारतावाद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस राज के जारिये हम सांस्कृतिक प्रदूषण का मकाबला करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अगर वास्तव में आप जनता को स्वस्थ संस्कृति देना चाहते हैं तो मंत्री महोदय ने क्यों ऐसा जल्दुरी समझा कि विदेशों के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं होगा? शायद उनकी नजर में विदेशी चीज अच्छी है। शायद हमारे उदारीकरण की यह मांग है, यह तकाजा है कि जो विदेशी चीज है वह अच्छी है। आश्चर्य होता है कि आज हमारा दूरदर्शन अपने चैनल से एमटीवी प्रसारित कर रहा है जिसको सारी दुनिया द्वारा स्वस्थ निगाह से नहीं देखा जाता। वह एमटीवी हमारे दूरदर्शन से प्रसारित हो रहा है। मंत्री महोदय यह दिखावा करते हैं कि हम संस्कृति को रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय की तरह काम कर रहा है। आज हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना हो गया है। इसके चलते आज हम यह देख रहे हैं कि हमारे दूरदर्शन का एक एक अणु किसी मंजन बेचने वाले, किसी पाउडर बेचने वाले, किसी साबुन बेचने वाले को बेच रखा है। ऐसे दूरदर्शनल से हम आशा कर रहे हैं कि वह केबल नेटवर्क को नियंत्रित करेगा, देश में स्वस्थ संस्कृति को देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंत्री महोदय जो अध्यादेश लेकर आये हैं उसमें हमें

बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हय केवल नेटवर्क को रेगुलेट करने की दशा में काम करेंगे। मैं इस बात को निश्चि रूप से मानती हूं कि केवल आपरेटर को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। जिस तरह से केवल आपरेटर्स की बाढ़ हमारे देश में आई है उसे नियंत्रित किया जाना जरूरी है। हमारा अनुभव रहा है कि इन केवल आपरेटर्स ने बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभाई, खासकर सांप्रदायिकता के भेद में। उन्होंने बढ़ावा दिया सांप्रदायिक तत्वों को। सांप्रदायिकता की आग को फैलाने में केवल आपरेटर्स आगे रहें। यह जरूरी है कि केवल आपरेटर्स हमारे देश में हमारे राष्ट्र के मूल्यों के तहत काम करें और इसके लिये उन्हें नियंत्रित किया जाना जरूरी है। इसीलिये मैंने वैकल्पिक संशोधन पेश किया है। (समय की घंटों) अगर भरा टाइम खत्म हो गया है तो मैं अपना संशोधन बाद में पेश करूंगी। जब बाद में संशोधन पेश करूंगी तो उस समय फिर उस पर अपने विचार रखूंगी।

**SHRI V. NARAYANASAMY** (Pondicherry) : Mr. Zice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Cable Television Network (Regulation) Bill, 1993. The electronic media in this country has undergone a revolution today. The hon. Minister has clearly mentioned in the Statement of Objects and Reasons that there is cultural invasion by the foreign media into this country and therefore the cable network that is being operated within the country has to be regulated. It should identify and maintain our culture. In the name of cultural invasion, it should not divide people as has been happening in the name of religion, caste, creed and so on. Sir, though it is a very simple Bill and I have stood up to support the Bill, yet I would like to make some suggestions to the hon. Minister. Electronic media is considered to be one of the vital elements of information and entertainment in this

country. The Cable Network which is being viewed by millions of people of this country has been invaded by foreign culture. The foreigners who have come and taken over the cable network are making huge investments on it. And their modalities and temperaments will, naturally, be in line with those of their countries. I was really surprised when the hon. Minister said that he would like to control the Western media in our country. It is highly impossible. You have allowed them to continue for years together; not only that, you did not have any regulations set for the foreign media in our country at the initial stage itself. I would like to give a small example.. Take the case of our neighbour, Pakistan. They are telecasting programmes which are totally anti-India and the people of our country are viewing them. What have you done about it? We protested against their actions at the diplomatic level, at the Ministerial level. But we are not able to counter the anti-India propaganda that is going on in Pakistan through the satellite network. Even on Doordarshan and through various other media, we are not effectively countering it, more so when they are doing it in order to damage our country's reputation and interests. This is only a small example which have given. Earlier, when I spoke on the discussion on the working of the Ministry of Information and Broadcasting, at that time itself, I mentioned as to how the vulgarity, terror and horror which are depicted through cable television network would affect minds of the younger generations of this country. The operation of the cable network, somehow, has not been regulated by any authority be it at the State level or at the Central level. I was really surprised when Mr. Jethmalani said that because of freedom of expression, freedom of speech and freedom of movement, the Government did not have any right or authority to control the media. I don't agree

with him. He may be a Constitutional expert. But I would like to say that the Central Government and the State Governments have got the regulating authority for protecting our country's culture. For defence purposes and also for keeping up the reputation of this country, the Government has got every right to regulate the electronic media in this country. Simply arguing on the basis of the provisions of our Constitution ignoring our country's interests, is totally unacceptable. It will only erode the patriotism which is prevailing amongst the people of this country.

Sir, day in and day out, we come across news items saying that Doordarshan would be introducing 49 to 50 channels. What is the purpose of bringing in so many channels? There is one peculiar thing. Clause 8 says: "Every cable operator using a dish antenna or a television receiver shall, from the commencement of this Act, retransmit at least one Doordarshan channel of his choice through cable services." Why do you insist on it? It is the choice of the viewers. It is the choice of the cable operator to beam programmes which they would like to see. If they want to see all the Doordarshan programmes let them see. Why do you bring in this clause and compel them that it should be transmitted or retransmitted? I don't find any logic in this. I agree with the Minister and also compliment him for the quality of the Doordarshan programmes has improved. Still we are not happy.

SHRI G. SWAMINATHAN  
 (Tamil Nadu): Because of competi-

SHRI V. NARAYANASAMY:  
 May be or may not be. Still I am not satisfied with the programmes that are being telecast by the Doordarshan. The programmes are not

up to make. They are not depicting. The culture of the people of this country. After watching the Star TV programmes, after watching the Zee TV programmes, Doordarshan is also going the same way. It is totally unacceptable. When you want to maintain your own separate identity, you do it. Let us not copy from the Star TV or Zee TV. Let us not copy the programmes of other networks and say that the Doordarshan has improved its quality. We have diverse cultures in various States in various regions, right from the Adivasi culture to the Western culture which you claim in the cosmopolitan cities. Let us not copy from the Western culture and say that the quality of the Doordarshan has been improved. And on this there is a lot of controversy. There is another controversy about which I would like to say. The hon. Minister said that they would like to telecast intellectual programmes on DD-3. Everyday you see a news item saying that this programme is being introduced from 15th August, 26th November, 1st January, etc. I don't know what these intellectual programmes are. I would like to know from the hon. Minister about this.

Another thing I want to submit is that I am really fed up with the regional programmes that are being telecast. Excepting cinemas, there is nothing in this. Some dramas are telecast in the regional programmes, whether it is West Bengal, Tamil Nadu or Karnataka. You know, the people are really fed up with these regional programmes. The housewives don't go away from the television. They see all the programmes on DD-3 and their household work is suffering. So, Mr. Minister, in the name of improving quality, don't go in for films only. Let us depict our culture. I have been saying this right from the beginning. Even the other day, I was telling the Minister about this. Kindly don't insist that people should see only the Doordars-

han programmes by bringing this clause in the Bill. Let the people see whatever they want to see. Let the people have their own choice. But I agree with you that the cable network has to be regulated. I am not going to ask you to compromise on this because the amount of obscenity that is there in the foreign programmes is just intolerable. You please tell me what you are going to do in regard to this. I must say that this foreign media is spoiling the Indian mind. The Indians living in New York and Washington want to send their children to India because they want their children to be spoiled because of the Western culture. But being the situation, why are you bringing the the Western culture here? You are bringing the culture here which our children would like. You want to bring a regulation and punish people who are smulish. Catch the big fish.

Another thing I would like to tell you is about the high rate of tax on cable networks. In various States, the rate of tax varies between 80% and 60%. There is no uniform policy. What will happen? The people, by and large, are being taxed. The viewers are being taxed. With 80% tax rate, the people are burdened. Mr. Swaminathan will definitely be affected because *(Interruptions)*

SHRI G. SWAMINATHAN: I have only one point. I would say that the Central Government is charging Rs. 50/- for the dish antenna. Now the State Government is the regulatory authority. So, they have to charge something to regulate it.

SHRI V. NARAYANASAMY: To regulate dish antenna it :

SHRI G. SWAMINATHAN: Because the Central Government can't regulate it.

AN HON. MEMBER: For the charging Rs. 250/- in Delhi.

SHRI V. NARAYANASAMY: Not only in Delhi, in Tamil Nadu they charge 40% tax. The cable opera-

tors there went on strike and ultimately they came to a 20% Swaminathanji, tell your State Government to reduce it.

SHRI G. SWAMINATHAN: You want cable TV to mushroom.

SHRI V. NARAYANASAMY: I don't want. But, the people who don't want to see the film is five or ten rupees, they will not... *(Interruptions)*...

SHRI G. SWAMINATHAN: No We have to regulate the T.V. Otherwise how do you regulate it *(Interruptions)* Regulation of the licensing; it is not understood the Government is regulating the Central Government is... *(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: I am telling you that for regulation, you have to implement it in the right spirit and that you have to do in the State Government. Therefore, Mr. Minister, let us not drift from the issue of cable invasion that is coming into this country. Let our D. D. darshan be connected to the country, as far as possible, try to see that we do not divide the people by showing films in the name of religion-Mathurji is also watching me—the name of caste and creed. The unified picture of our society is depicted to the people. That emphasis should be there. And, by bringing the legislation, I accept that only a limited purpose will be solved. You are doing a lot of things in this regard. Mr. Minister, are you hearing me? Mr. Minister, you have to do a lot of things in this field. The foreign media should not be allowed to take over our Indian culture. Then, our country's security is also important. Then, you have to counter Pakistan's anti-India propaganda in an effective manner. These are the things that

you have to do. So, I support this legislation. But you have to do a lot of things in the field of electronic media, especially to counter the foreign media. Therefore, I support you in this and I want you to do that.

**SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI** (Tamil Nadu) Mr. Vice-Chairman, Sir, This Bill has been brought on the pretext of regulating the cable-TV operators. At the outset, I want to enlighten myself through the reply and clarification of the hon. Minister.

Sir, I want to know under what entry number and under what List of the Constitution, this Bill has been brought. Is there any legislative competence to bring this Bill because the Government of Maharashtra and the Government of Tamil Nadu have already brought Bills imposing levies on the cable TV operators and asking them for Security Deposits ?

Sir, they have done so under Entry No. 33 of the Seventh Schedule of the Constitution, that is, when they are bringing it under Entry No. 33, they consider it as 'Entertainment and Amusement'. Therefore, I want to know whether you have any legislative competence to bring forward this Bill. This is an important issue because when the matter came up before the High Court, it upheld the State law. Now, if the Centre is going to pass this Bill, I know ultimately the Central law will prevail. I fear that it is not in the Concurrent List. Therefore, I wanted to be enlightened from the reply. Sir, regarding the registration, the Government says that they are the registration authority. But, we did not know who is the registration authority. Only yesterday we got some papers through which we found that the Post—

Masters are the registration authority. The State law asked the cable operators to register themselves in the nearby police station by paying Rs. 10,000 as deposit and they must agree to pay 40% tax that goes to the court. It is in the stay order. In the stay order the amount of Rs. 10,000 has been reduced to Rs. 5,000. And also the registration authority is in question. But it has upheld it. But, against the State Government, In think, it has gone to the Supreme Court. Sir, this is the situation. You say that you must go to the Post-Master and the State Government says that you must go to the police officer. I want to know whom they have to approach for getting themselves registered. That is the problem. Then, Sir, they have to pay Rs. 10,000, for even 40% tax—entertainment tax is only 20%. Suppose the same law is upheld by the court again they may have to shell out 40%. That means you are firing from the front side and the State Government is firing from the rear side. In between are sandwiched the cable operators. This is the real situation. Sir, when you say that the registration authority is the Post-Master, I can tell you that there is already a heavy workload in the post-offices. There is a heavy workload because you have put a ban on recruitment. They are fighting against that.. (Interruptions).

Let them fight some other authority. Before coming to the Bill, I wanted to state that basically I differ from the Bill. Now, coming to the Bill, in clause 5, you have emphasised and stipulated for a programme code and an advertisement code. People from remote villages who are unemployed have to resort to this for jobs. Do you think that these people will be aware of these programme codes and advertisement codes. Till the day before yesterday, I was

not aware of the programme code and advertisement code. . . (Interruptions). . . I could not get in the Secretariat. Yesterday though the Parliament papers we were able to get it. When the parliamentarians are struggling for nearly one week to get the programme code and advertisement code, do you think that people who are operating the cable network would be aware of it ? It is unnecessary, I feel. I want to know whether you are adhering to the codes on the T.V. itself. Now-a-days, you are telecasting the 'Directors' Special'. I want to know what this 'Directors' Special is. You are violating the code which you have prescribed yourself. I shall quote only one paragraph which was published in the *Indian Express* dated 9th November, 1994. It says, I quote :

"In a major policy change the Doordarshan has been allowing indirect liquor and cigarette advertising on the national network and the Metro channel for the last two months" It goes on like this. There is no denial coming from the Government side. Actually, the implied meaning of that is that the Government has accepted this.

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) : On Doordarshan the liquor advertisement comes after every four minutes consistently during test match commentary.

SHRI VAYALAR RAVI : We all share the sentiments of the hon. Member. It should be stopped immediately.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : I agree with you, Sir. Thank you for that. I want to know whether there are two codes' one for the cable operators and another for the Doordarshan. Sir, the same provision under clauses 5 and 6

you are exempting the foreign satellites for telecast. Here we want to know why you want to exempt them. It is a step-motherly treatment and it is discriminatory. Then, Sir, under sub-clause. . . (Interruptions). . .

SHRI VIREN J. SHAH : Sir, the liquor advertisement is coming on Doordarshan after every three minutes. Hon. Minister, in your absence it was mentioned that tobacco and liquor advertisements are coming every four minutes when there is cricket commentary. The hon. Member from your side also supported it that it should be stopped.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : It clearly shows you are violating the code. This is nothing but a step-motherly attitude. That is what I want to charge against you.

Sir, in sub-clause 7 you want to make a registration. It is not possible for a layman. That is why I want to say before telecasting how he should be able to know as to what is going to be telecast. Then you are telling that you are not actually violating the code. You want to punish it is what I feel. It is impossible. It is actually illogical. I am unable to comprehend on what grounds you have put this condition.

In sub-clause 8 you say that TV retransmission that is what Shri Narayanasamy also told—you should not compel. Why do you want to compel the cable operators to retransmit the DD ? I would like to tell that because of this unimaginative poor, show the people, are switching over to others. People are switching over to the others because of this poor performance. The programme is so poor, the programme is so unimaginative, it is boring and even if it is fair, people from east to south are not prepared to cope with the DD. Another thing

[Shri S. Viduthalai Virumbi]

is that when you are stimulating all these things You have left out one provision. You are imposing Hindi day in and day out.

What is the necessity, why is it essential ? I want to know, when from Kashmir to Kanyakumari India is one, going to allot the same time to other languages also ? All the languages should be given equal status, equal treatment. I want to know whether you are giving the same time to Tamil, to Gujarati, to Malayalam, to Marathi ? For all the languages equal time should be given. If you want to give four times more than what you are giving to other languages to Hindi it clearly shows that it is yet another domination worse than the British domination. Why there is no provision against this ?

THE VICE CHAIRMAN :  
 (Suresh Pachouri): Please conclude.

AN HON'BLE MEMBER :  
 What about English ?

SHRI S. VIDUTHALAI VIR-  
 UMBI : English has integrated this country. You should not forget that. Netaji Subhash Chandra Bose talked to the people of Bombay in English and not in Hindi. I want to submit one more thing. Once a letter came to Rajaji in Hindi and that too from Gandhiji. Rajaji on the reverse of the same letter wrote the reply in Tamil. Mahatma Gandhi felt it and he actually tendered his regret for that. I would like this to go on the official record.

श्री वल्लभ नारायण सारंग : (मध्य प्रदेश) : इसलिये आप संसद में बोलिये । अगर हिन्दी के पक्ष का उत्तर राजाजी तमिल में दे रहे हैं तो आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं ? तमिल में बोलिये,

यहां इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था है । आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं ?

SHRI S. VIDUTHALAI VIR-  
 UMBI : Because of this policy... (Interruptions)... We want to see India and not *Hindia*.

SHRI S. K. T. RAMACHAND-  
 RAN (Tamil Nadu) : But we want to see Cable T V. We do not want to go... (Interruptions)...

श्री रामशास् अन्नवाल (राजस्थान) :  
 उपसभाध्यक्ष जी, यह 'केबल' वाला मामला चल रहा है या हिंदो-अंग्रेजी का चल रहा है ? आप हिंदो-अंग्रेजी को छोड़कर अपनी बात कोजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (Shri  
 Suresh Pachouri) : Please conclude  
 now, You have already taken 12  
 minutes.

SHRI S. VIDUTHALAI VIR-  
 UMBI : I am concluding, Sir. Before  
 you want to implement this, consult  
 the State Governments. Leave the  
 matter to the State Governments.  
 Don't try to encroach upon the rights  
 of the State Governments. And  
 also just think about the Prasar  
 Bharati Bill which was introduced  
 but not yet passed.

With these words, I want you to  
 please let me know in what List, in  
 what Entry, you want to pay for this  
 and whether you have got the legisla-  
 tive competence to bring forth this  
 Bill.

With these words, I thank you,  
 Sir.

SHRI VAYALAR RAVI : That  
 you have to say before the introduc-  
 tion, and not now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
 SURESH PACHOURI) : Shri  
 Kulabidhu Singh.

**SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) :** For the information of Mr. Virumbi, I want to say one thing about Rajaji. Rajaji was the Chairman of the all India Hindi Pracharak Samiti. He was the person who had toured the whole of South for Hindi prachar.

**SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI :** In 1965, Rajaji said that he had changed his mind because the Northern Indians wanted to impose Hindi. That is why he was one of the persons who opposed Hindi in 1965.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) :** We are not discussing the language issue.

**SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI :** From 1957, he started opposing Hindi.

**SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN :** Sir, we are deviating  
...Interruptions)

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) :** Nothing will go on record. Now Shri kulabidhu Singh.

**SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur) :** Mr. Vice-Chairman, Sir, Shrimati Kamla Sinha was to speak on behalf of my party, but as she is not present, I want to make certain very limited observations.

Sir, the hon. Minister had stated that the objective of the Bill is to protect our culture against foreign invasion. Regarding that, of course, I support this Bill, by and large, but I want to make certain observations. Sir, the invasion of foreign media and foreign culture is already there even in our National Channel now. So, this point of talking about foreign invasion of our culture is not very meaningful. Already the invasion is there in all national programmes. All sorts of western obscenity and western vulgarity are visible. Day in and day out, we are witnessing these vulgar

scenes and obscene scenes in our National Channel-2. So, this is a nice word, but practically invasion had already taken place. Moreover, I want to mention another aspect. This is the time for freedom of thought and freedom of conscience. Whatever be the invasion, if the persons who receive it at the receiving end, if they can only understand and appreciate the thing, this foreign invasion will not alter much of our culture.

Secondly, Sir, Mr. Virumbi was telling about the language. Only a sentimental tussle is going on between our friends over her and our friends over there because the three-language formula is already there. Nobody can prevent any citizen from speaking English. Regarding translation, Mr Sarang was making a point. Sir, the Manipuri language was included in the Eighth Schedule the year before last. We pressed for keeping an Interpreter. I have time and again requested the authorities for the appointment of one Interpreter for the Manipuri language, but it is not permissible because of the financial limitations. So, as there is no Interpreter for the Manipuri language in this House or in the Lower House, we cannot abandon speaking in English.

**SHRI G. SWAMINATHAN :** Sir, if there is no translation available in one language, can a Member of the House translate for another Member?

4.00 P.M.

**SHRI W. KULABIDHU SINGH :** We have been pressing for an interpreter. We are three Members; two in the other House and one here. We are facing a great problem. When Manipuri had been included in the Eighth Schedule of the Constitution, I do not know why we should not get an interpreter. This is the problem. Therefore, I think those who hate English should not mind if people like us speak in English.

Thank you.

**SHRI G. SWAMINATHAN:**  
 Mr. Vice-Chairman, Sir, within the very short time available, I would like to make some points. Of course, these points had already been made by some of the Members who spoke earlier, but I would throw a new light on them, if possible.

First of all, I would like to stress on one important point to which a reference had been made earlier by the hon. Member, Shri Ram Jethmalani. He was talking about the mushrooming of cable television networks and queried as to how you were going to prevent this mushroom growth. In the Statement of Objects and Reasons of the Bill, you have outlined three objectives, i.e. curbing the mushrooming of cable television networks, stopping the cultural invasion and improving the quality of the programmes. You say that you are bringing forward this Bill to achieve these three objectives.

As has been rightly said by Mr. Ram Jethmalani, when one goes through the Bill, one does not find anything in this regard. Where are the provisions by which the hon. Minister would be able to stop this cultural invasion, for example? Where are the provisions by which you are going to achieve the three objectives outlined in the Statement of Objects and Reasons of the Bill? I have not been able to find any.

However, I have risen to support this Bill for a limited purpose. I support the Bill because you are providing for the registration of cable television operators. Even though I do not find any provision in the Bill to check the mushroom growth of cable television networks or to stop the cultural invasion, about which you have been talking all along. I support this Bill because you are making registration absolutely necessary. Otherwise, if you do not have a system of registration of the cable television operators, you would not be knowing

as to how many of them are there and they would be outside the purview of this Bill. From that point of view, I support this Bill.

Then in regard to quality, if you want to maintain and improve the quality of the programmes, you should first of all, see that there are good programmes in your own Metro Channel. As has been said by our friend, the very things about which you are concerned which are being shown in the cable television—are there in your own Metro Channel. What kind of films and other programmes are there in the Metro Channel? There is so much of violence. There is so much of sex. Therefore, unless Doordarshan itself acts as a model, you would not be able to control these cable television operators and you would not be in a position to stop the cultural invasion. I hope the hon. Minister would take up this matter very seriously so that Doordarshan acts as a model.

According to me, one main reason for bringing forward this Bill is the declining market share of the advertisement revenue for Doordarshan. The cable television and the satellite television operators are taking a way much of the advertisement revenue because their rates are not as much as in the case of Doordarshan. That is why Doordarshan is finding itself in a difficult position. Unless Doordarshan improves its operation and does something about it, it will not be able to improve its market share of the advertisement revenue. This seems to be one of the things which is forcing Doordarshan.

I would now like to say something about the penal provisions. Here, you are giving the powers to an officer. This point has been made already by a Member from the Congress Party. You say here, 'two years' or 'one thousand rupees' and 'five

years and five thousand rupees. This has no meaning because when you say 'five thousand rupees', it is not *status quo*. One can go up to five thousand rupees. A magistrate or some judge may fine a person to the extent of Rs. 1,500/-, Rs. 2,000/- or Rs. 2,500/-. Nowadays, the value of Rs. 2,500/- or Rs. 3,000/- is not much. Therefore, I would say that you should rethink about these penal provisions. I say this because on the one side, the imprisonment is heavy and on the other, the fine is very small. There should be some equity in this. This is the point I would like to make in respect of this matter.

Coming to the question of a third channel, you have been talking much about it. My friend, Mr. Narayanasamy, had also referred to it. He was asking as to when you were going to introduce the third channel. The hon. Minister recently visited Madras. It had appeared in the Press, in the 'Hindu'. The Minister has been talking about having as many as 60 channels in Doordarshan. In this connection, I would like to invite the attention of the Minister to the editorial which had appeared in the 'Hindu' and I would like to know his reaction on the matter. The editorial had asked as to what was the meaning of the Minister talking about 60 channels when he had not been able to introduce even the third channel in the country. This has to be gone into. I do appreciate the sentiments underlying the Objects of the Bill.

But I feel that there are no teeth available in the Act or in the rules to implement the same. I feel that the order of the Doordarshan credo of education, information and entertainment is not proper. The credo of the private cable networks is entertainment first, then information and the third is education. In India, more people now want entertainment because they cannot afford cinema.

Cinema tickets have become so costly now. Entertainment is also very important for TV, and I hope Doordarshan will give good and clean entertainment to the people so that people will be very happy to go in for it.

One more thing that I will add is that the cable operators are not giving quality programmes, and also there is no competition among the cable operators. In my place there is only one cable operator who is operating. And these people have a cartel. They talk to each other and they will not allow another operator to go into that locality. The localities are divided in Madras. Suppose you are in Kilpauk, that locality is taken over by one cable operator. Purasawakam is taken over by another cable operator. So, any other man will not be allowed to go into those territories. So the house-owners do not have any other recourse except to go to that particular cable operator. So I would request the Minister to see, through these rules and the Act, that two, three competitor cable operators in each area. Otherwise, if you allow only one man, he will not be able to give quality pictures to the people. So I request that the Minister should think in terms of competition, competition in the interest of giving quality pictures to the people so that they will be able to switch over from one man to the other.

I also agree with the other hon. Member, finally, that it is not necessary for Doordarshan to say that at least two channels of Doordarshan should be telecast by the cable operators. The cable operators are coming in only as competitors. So this is not necessary and this condition must be removed. That is what I feel.

Generally, while appreciating the sentiments of the Minister, I feel that something more has to be done about the rules and the Act.

SHRI K. R. MALKANI (Delhi):  
 Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Statutory Resolution moved by my good friend, Mr. Viren J. Shah. I find that this Ordinance about cable TV Network has many loose ends. These loose ends need to be tied up. I also find that it has some gaping holes, and these holes need to be plugged.

First, about the loose ends. A person may apply, but the law does not lay down how soon the decision may be taken. I think an upper time limit should be fixed here, whether the man will hear within one month, two months, three months, six months or whatever. We cannot give an indefinite, arbitrary power to the registering authority in this regard.

Secondly, in the definition of "cable operator" we need to add the words "a person who is running this activity as a "commercial activity" because some private company or some educational institution carrying on programmes should not be governed by this law.

Then, there should be a right to second appeal. One appeal is not enough.

Then, clause 19 says that a punishment may be imposed or a registration may be cancelled for reasons a, b, c, or any other reason. I think this is much too vague and gives too much opportunity of exploitation to the registering authority. Here it must be made clear that when registration is refused or punishment is imposed, the authority must give the grounds and record them in writing.

As I said earlier, there are some gaping holes in this law. The government has announced a programme code, an advertising code. That is fine.

But who is going to monitor these programmes? Does the Government have any monitoring authority, any agency which will take note of what is happening in the cable TV networks? I know, we all know, as our good friend, Mr. Narayanasamy has pointed out, that there are cable TV networks in India putting out programmes prepared by Pakistan, propaganda programmes on Kashmir etc. What is the Government doing about it? This Ordinance, this law, has been in operation for almost three months now.

Is the Government aware of this programme? Has it taken any action? If not, why not? So, unless there is a monitoring authority, monitoring agency, just prescribing a programme code is pointless.

Secondly, this law lays down that the applicant will have to be an Indian citizen. That is okay. But, this law also permits that 49 per cent of the equity may be owned by foreigners. Is there not a serious contradiction between these two provisions?.. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Order, please. Yes, Mr. Malkani.

SHRI K.R. MALKANI: It can very well happen that foreigners controlling 49 per cent of the equity will be the real masters, and the other shareholders may have 1 per cent, 2 per cent or 5 per cent of it. So, the application may come from an Indian, but it will be practically a *benami* transaction. If the Government is serious about keeping out all foreign influences in this matter, I would suggest that they come out frankly and say that it will have hundred per cent Indian equity. What to talk of 49 per cent, they should not be allowed even 4 per cent. If you are serious about protecting our national life our culture etc., then, this is a much

I am glad that the Prime Minister yesterday said that we should be careful about too much foreign capital coming into wrong kinds of fields. This is one field where foreign capital will be very wrong. So, if the Government is serious about keeping these undesirable influences, foreign influences out, then, the equity must be 100 per cent Indian.

There is a strange provision in this Ordinance. It does not cover programmes issued by cable TV networks if these programmes originate in some foreign countries. Government seems to be under the impression that if something originates abroad, it cannot be controlled here. It can be under the law. The reality is that these foreign cable networks and foreign TV networks have been blatantly violating international telecommunication agreements. Here I would like to quote my good friend, Mr. Krishan Lal Sohni, who has done a study of foreign media invasion of India. He makes it very clear. He says.

“Under international telecommunication agreements, TV signal has to be broadcast on a particular frequency band called “C band” or a very high frequency of “KU band” with the proviso that footprints of the transmission must remain within the country of its origin. It can spill over to neighbouring countries only if broadcasting under the “C band” which is a telecommunication. But Star TV and other TV have started telecasting to dozens of countries without so much as by your permission. This is a clear violation of international telecommunication agreements.

I hope the Government takes note of it. I am sorry to say that the

Government has shown a certain lack of vision and a certain lack of will in handling this and related matters.

Thank you very much, Sir.

श्री जलाल दोन खंसारी (बिहार) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन उद्देश्यों को लेकर यह बिल लाया गया है और उसमें जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को देखने से पता चलता है कि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने वाली है। यह स्पष्ट है कि विदेशी मोडिया के जरिये हमारे देश को सांस्कृतिक परम्परा रही है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, उन पर प्रतिक्रिया किया जा रहा है। लेकिन इस सांस्कृतिक प्रतिक्रिया को रोकने के बिना हमारी सरकार को जो इच्छा शक्ति होनी चाहिये, वह इच्छा शक्ति है ही नहीं और इसके पाछे कारण यह है कि जिस उदार नीति का इन्होंने पालन किया है आर्थिक क्षेत्र में, वह आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गया है, हमारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साइंस एंड टेक्नालॉजी के क्षेत्र में भी इस उदारतावाद को नीति ने आज हमको यहां तक पहुंचा दिया है कि हम विदेशी मोडिया के प्रतिक्रिया को रोकने में सिकुट हो गए हैं। लाये हैं, उसके जो भी प्रभाव है, उसको यदि देखा जाये तो यह प्रभाव हमारे नियंत्रण के अन्दर है। दूसरी बात है कि आप कानून टेलेविजन नेट वर्क रेगुलेट एक्ट, 1993 को लाये हैं तो इसमें कुछ अच्छा बातें जरूर हैं लेकिन जिस दिन बिल पेश किया जा रहा था, उस दिन भी यह मांग उठायी गयी थी कि कोटी की व्यवस्था विधेयक के अन्दर होनी चाहिये। जो रूल्स फ्रेम

किये जायें, वह विधेयक के अन्दर हों। आप कहते हैं कि केबल आपरेटर्स का पंजीकरण पोस्ट ऑफिसिस में किया जायेगा तो इस तरह के जो केबल आपरेटर्स होंगे, उनकी दिशा क्या होगी? हम यह समझते हैं कि जिन केबल आपरेटर्स को आप अपने काम में लेना चाहते हैं, उनका पंजीकरण तो होना चाहिये लेकिन उनके लिये एक विशेष प्रशिक्षण और विशेष शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह एक निश्चित दिशा में केबल आपरेटर्स के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रमों को दिखाया करें। उनकी एक निश्चित दिशा हो। यह दिशा विहीन कौन-सा कार्यक्रम दिखायेंगे? दिशा-विहीनता से काम नहीं चलेगा इसलिये हमारा यह आरोप है कि हमारा दूरदर्शन उपभोक्ता संस्कृति का शिकार हो गया है और हमारे मित्रों ने सही कहा कि जो भी प्रोग्राम दिखाये जाते हैं, उसके बीच में यह विज्ञापन दिखाते हैं जिसकी वजह से कार्यक्रमों का तारतम्य टूट जाता है और उपभोक्ता संस्कृति का शिकार यह दूरदर्शन सही मायनों में शिक्षा का काम या प्रचार का काम नहीं कर सकता है और विदेशी उपग्रहों के माध्यम से जो हमारे मीडिया पर प्रतिक्रिया किया जा रहा है, अश्लील गाने दिखाये जाते हैं, अश्लील चित्रों को दिखाया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिये इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम समझते हैं कि आप भारतीय परम्परा की रक्षा करते हुये नयी पीढ़ी को (विदेशी) पाश्चात्य सभ्यता के दुर्गुणों से बचाने के लिये केबल नेटवर्क का प्रोग्राम

हो, इसको इतना मजबूत बनाइये, इतना प्रभावशाली बनाइये ताकि वह हम पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम उनको रोक सकें। इसके लिये कानून में भी व्यवस्था होनी चाहिये, यह हमारा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

شرعی جلال الدین انصاری «بہار»  
اُپ اویٹکیشن مہودے۔ جن اڈیشیوں کو  
نے کر یہ بل لایا گیا ہے تو اس میں جو  
پراؤدھان ہے۔ ان پراؤدھانوں  
کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اڈیشیوں  
کی پورتنی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ سیشٹ  
ہے کہ وڈیشی منڈیوں کے ذریعہ ہمارے  
وڈیش کی جو سانسکریٹک پر میرا رہی ہے۔  
جو ہماری سانسکریٹک وراثتیں ہیں  
ان پر اتیکر من کیا جا رہا ہے لیکن  
اس سانسکریٹک اتیکر من کو روکنے کے لئے  
ہماری سرکاری جو اچھا شکلی ہو فی  
چاہئے وہ اچھا شکلی ہے ہی نہیں اور  
اس کے بجائے کاروبار ہے کہ جس ادارہ  
نیٹی کا انٹرنل نے پاس کیا ہے آرتھک  
اکشیر تک ہی اہمیت نہیں رہ گیا ہے۔  
ہمارے سانسکریٹک - شیکشٹیک -  
سائنس اور ٹیکنالوجی کے اکشیر میں بھی  
اس ادارہ واد کی نیٹی نے آج ہم کو

یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم وڈیشی میڈیا کے اٹیکرمن کو روکنے میں دھچک رہے ہیں۔ کہ جو بل لائے ہیں اس کے جو انچھید ہیں اس کو یدری دیکھا جائے تو کہیں بھی اس کو روکنے یا مینٹرنٹ کرنے کی ویو سسٹھا نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسبل فی۔وی۔ نیٹ ورک ریگولیشن ایکٹ ۱۹۹۳ء کو لائے ہیں تو اس میں کچھ اچھی باتیں ضرور ہیں لیکن جس دن بل پاس کیا جا رہا تھا اس دن بھی یہ مانگ اٹھائی گئی تھی کہ کوڈ کی ویو سسٹھا ودھیک کے اندر ہونی چاہیے جو رولس فریم کئے جائیں۔ وہ ودھیک کے اندر ہوں۔

آپ کہتے ہیں کہ کیسبل آپریٹروں کا پنچیکرن پوسٹ آفیسرز میں کیا جاملے گا تو اس طرح کے جو کیسبل آپریٹرز ہوں گے تو ان کی دشا کیا ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کیسبل آپریٹرز کو آپ اپنے کام میں لینا چاہتے ہیں ان کا پنچیکرن تو ہونا چاہئے لیکن ان کے لئے ایک ویشس پرنشیشن اور ویشس شکشا کی بھی ویو سسٹھا ہونی چاہئے تاکہ وہ ایک نشیجٹ دشا میں کیسبل آپریٹرز کے روپ میں دور درشن کے کار یہ کرموں کو دکھایا کریں ان کی ایک نشیجٹ دشا ہو۔ یہ دشا وہیں لوگ کو نسا کار یہ کرم دکھائیں گے۔

تو وڈیشا دہینتا سے کام نہیں چلے گا۔ اس لئے ہمارا یہ آر اوپ ہے کہ ہمارا دور درشن آپ بھوکٹ سنسکرتی کا شکار ہو گیا ہے اور ہمارے مٹروں نے صحیح کہا ہے کہ جو کبھی پروگرام دکھاتے جاتے ہیں اس کے بیچ میں یہ وگیا پن دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے کار یہ کرموں کا ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ بھوکٹ سنسکرتی کا شکار یہ دور درشن صحیح معنوں میں شکشا کا کام یا پرچار کا کام نہیں کر سکتا ہے اور وڈیشی آپ گروہوں کے مادھیم سے جو ہمارے میڈیا پر اٹیکرمن کیا جا رہا ہے۔ اٹلیں لگانے دکھائے جاتے ہیں اسے اٹلیں چپٹروں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس پر روک لگانے کے لئے ان کے پاس کوئی ایسی ویو سسٹھا نہیں ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھارتیہ پر میرا کی رکشا کرتے ہوئے نئی پٹری صی کو وڈیشی پاشیچا تہ سبھتا کے دور گنوں سے بچانے کے لئے کیسبل نیٹ ورک جو پروگرام ہیں اس کو اتنا مضبوط بنائیے۔ اتنا پر بھاؤ شالی بنائیے تاکہ وہ جو ہم پر اٹیکرمن کر رہے ہیں ہم ان کو روک سکیں۔ اس کے لئے قانون میں بھی ویو سسٹھا ہونی چاہئے۔ یہ ہمارا سمجھاؤ ہے ان ہی تبدوا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

”ختم شد“

**श्री मूलचन्द मोणा (राजस्थान) :**  
उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा केवल टेलीविजन नेटवर्क बिल 1993 प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में हिन्दुस्तान पर इसका असर हुआ है। संस्कृति के ऊपर ही यह हमला नहीं है बल्कि आर्थिक और राजनैतिक हमले की भूमिका भी इस से बंधती है। पिछले दिनों विदेशी संस्कृति के वर्चस्व जमाने के अनेक कदम उठे हैं। अनेक तैयारियाँ चल रही हैं। विदेशी अखबारों के प्रवेश के लिए देश के अंदर बहुत बहस हुई है लेकिन विदेशी जो फिल्में हैं, विदेशी टी.वी. कम्पनियाँ हैं उनके प्रवेश के ऊपर चर्चा न होने के कारण आज यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी है। पिछले मई महीने में अमेरिका की कम्पनी इस देश के अंदर सी.आई.सी. नाम से आई थी। वह अपनी देश के अंदर 43 शाखाएँ खोल चुकी है और 2100 करोड़ रूपए सालाना का कारोबार है। यदुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों का एक ही उद्देश्य रहता है कि जिस कारोबार को अपने हाथ में लेते हैं उस कारोबार को विलय, अधिग्रहण, गठबन्धन, अनुबन्धन आदि के जरिए वर्चस्व स्थापित करना उनका एक मात्र उद्देश्य रहता है। आज इस देश के अंदर जो केवल टी.वी. आपरेटर्स हैं, छोटे आपरेटर्स हैं उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, उनको खरीदने के लिए एक ऐसी योजना कम्पनियों के द्वारा बनाई गई। इसी के लिए मंत्री महोदय द्वारा यह अध्यादेश सितम्बर महीने में लाया गया और यह पार्लियामेंट से पास कर विधेयक बन जायेगा। लेकिन देर में ही सही आपने इस विधेयक को लाकर छोटे केवल आपरेटर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। विदेशी टी.वी. नेटवर्क द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम दिखाये गये हैं जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। जो हिन्दुस्तान के रहन-सहन, हिन्दुस्तान की कल्चर से मेल नहीं खाते। अवांछनीय प्रोग्राम देखने को मिलते थे। इससे हमारी जो मूल संस्कृति थी, उसकी जो भावना थी उस पर एक प्रकार से हमला उन कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। यह हमें पाश्चात्य संस्कृति की

ओर झुका लेती है। जो हमारी नई जनरेशन है, जो छात्र वर्ग है वह स्कूल के बाद रोज टी.वी. से बिपका रहता है विदेशी नेट वर्क के माध्यम से जिन्हें हम अशोभनीय दृश्य कहते हैं, हमारी संस्कृति में जिनको बुरा माना जाता है उनको दिखाया जाता है। इसका प्रभाव हमारे यहां के छात्रों पर, आने वाली नई जनरेशन पर पड़ता है। उनको रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए मेरा कहना है कि मंत्री महोदय का उद्देश्य अच्छा उद्देश्य है। अब से पहले जो केवल टी.वी. नेटवर्क का प्रचलन था वह किसी तरह से नियंत्रित नहीं था। गंदी से गंदी फिल्मों को भी केवल टी.वी. नेटवर्क के माध्यम से दिखाई जाती थीं। आज से इस विधेयक बनने के बाद इस पर रोक लगेगी। क्योंकि केवल टी.वी. आपरेटर्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इस विधेयक के अंदर की गई है। साथ ही जो हमारी संस्कृति का अतिक्रमण करेगा, जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती उनको दिखाने का प्रयास करेगा, बिना स्वीकृति के केवल टी.वी. आपरेट करके दिखायेगा उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था भी इसके अंदर की गई है। इस बिल में यह भी व्यवस्था है कि अवांछनीय कार्यक्रम नहीं दिखाये जायेंगे। इसको कार्यक्रम कोड धारा-5 के अंदर बताया गया है। कार्यक्रमों के नियमों को क्रम-बद्ध बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे लोगों को वास्तविक रूप से टी.वी. से जो ज्ञान प्राप्त होना है वह हो सके। दूसरा, विज्ञापनों को आज केवल टी.वी. वाले जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको इसमें दिखाया जा रहा है, हमारी इच्छा न होते हुए भी जो विज्ञापन पैसा कमाने की इच्छा से इस तरह से दिखाये जा रहे हैं, उसका हमारे ऊपर गलत असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको नियमित इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। इसमें व्यवस्था है कि जो भी विज्ञापन दिखाया जाएगा, उसे पहले दिखाया जाएगा और स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही दिखाया जा सकेगा, उसके बाद ही उन विज्ञापनों को प्रसारित किया जा सकेगा।

महोदय, केवल आपरेटरों की सुरक्षा की भावना से यह बिल लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है—क्योंकि जो छोटे केवल आपरेटर्स हैं उनको बड़ी बहु-राष्ट्रीय कंपनियां देश के अंदर आयी हैं, वह उन्हें अपने कब्जे में करने के लिए इनको उनसे खरीद लेती हैं और अपने इच्छानुसार पैसा संस्कृति बनाने वाली फिल्में इस नेटवर्क के माध्यम से दिखाना चाहती हैं। आज इस देश के अंदर 10-15 टी.वी. चैनल हैं। लेकिन धीरे-धीरे बढ़कर, 1995 में ये करीब 50 होने जा रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक हो गया था। इससे केवल आपरेटरों की सुरक्षा के साथ-साथ इस देश की संस्कृति की सुरक्षा भी होगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अवांछनीय कार्यक्रम अब तक इन केवल टी.वी. नेटवर्क के माध्यम से लोगों को देखने के लिए मिलते थे, उस पर इस बिल के माध्यम से जो प्रतिबंध का प्रावधान आपने इस बिल के माध्यम से किया है, मैं यह मानता हूं कि इससे अवांछनीय कार्यक्रमों से हमारे लोगों को सुरक्षा मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेंगे जिससे हमारी संस्कृति पर कोई हमला होता हो। साथ ही इस बिल के अंदर आपने यह भी व्यवस्था की है कि केवल आपरेटर्स टी.वी. नेटवर्क में जो भी उपकरण लगावेंगे वे सब भारतीय मानकों के होंगे। ऐसा प्रावधान करने से जो ऐसी कंपनियां हैं जो इन पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती हैं और अपने उपकरण सप्लाई करना चाहती हैं, उनसे इनको बचाने के लिए आपने यह प्रावधान किया है। यह कदम भी स्वागत योग्य है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी ने जिस भावना के साथ इस बिल को प्रस्तुत किया है उसी भावना से वह तत्परता से इसको लागू करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष जी, आज से दो-तीन साल पहले जब हम लोग इस उदारीकरण का विरोध कर रहे थे, जो आज की सरकार चला रही है तो हमारे बहुत से लोगों को, खास करके जो कांग्रेस के लोग हैं उनको हमसे बड़ा विरोध था। हमने कहा था कि सरकार चाहे तो “एम” टी.वी. और स्टार टी.वी. चलाए लेकिन अगर यह संस्कृति चलाती है, स्टार टी.वी. चलाना है तो सीता और सावित्री संस्कृति इस देश में नहीं चल पाएगी। उस समय कुछ लोगों को यह मजाक लगता था। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सरकार खुद इस बात को सोचने पर मजबूर हुई और उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रकार का एक बिल सरकार ने सदन में पेश किया है। लेकिन यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है यह बिल अपने आप में बिल्कुल अधूरा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार के किस विभाग ने, कानून के किस दायरे में इस बिल को बनाया है और किन प्रयासों से उस मजिल तक सरकार पहुंचना चाहती है जो सरकार इस बिल में कह रही है। अभी अचानक सारा जो कुछ मामला बिगड़ा है, दूरदर्शन से या आपन स्काई नीति से इसका एक अहम मुद्दा सरकार के सामने और इस सदन के सामने है। पाकिस्तान द्वारा ऐसे प्रचार माध्यम अपनाए गए हैं जो इस देश में नहीं दिखाए जा सकते हैं। दुनियां को कहने से रोकने के लिए सरकार समझती है कि यह तरीका उनके लिए सही तरीका हो सकता है।

माननीय मंत्री जी, मैं भी कभी-कभी पाकिस्तान टेलीविजन देख लिया करता हूं। सारी बातों को छोड़ दीजिए, एक प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन पर आता है, उसमें आपके सेंसर बोर्ड से पास किए हुए दो कार्यक्रम आई. विटनेस और न्यूज ट्रेक हैं। भारत विरोधी कार्यक्रम में इन दो माध्यमों से जो आपके सेंसर बोर्ड द्वारा पास किया हुआ है, वह प्रसारण देखने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने कार्यक्रम में न सिर्फ सफल सिद्ध हो रहा

[ श्री दिग्विजय सिंह ]

है बल्कि दुनिया में जहां हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, वहां हमारे पास कोई जवाब नहीं है। भारत के सेंसर बोर्ड के द्वारा पास किया हुआ कार्यक्रम पाकिस्तान के पक्ष में जाता है, भारत के विरोध में जाता है। आप इस बात की गम्भीरता को समझने की कोशिश कीजिए। उदारीकरण की जो हवा बहाई जा रही है, उसका असर सिर्फ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का मामला नहीं है बल्कि उसका असर दुनिया की उन बड़ी-बड़ी ताकतों के पास है जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को लड़ा कर दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं। इसलिए हमने शुरू में इस उदारीकरण का विरोध किया और यह कहा था कि इस उदारीकरण से इस देश का कोई हित होने वाला नहीं है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे खुशी है कि आपने इस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास किया है। लेकिन इस बिल में बहुत कम ताकत है। क्या होगा इस बिल के माध्यम से? कहां रोक पाएंगे, कितनी आपकी सीमा है? इस बिल में जो ताकत होनी चाहिए थी, उस ताकत और बल का अभाव मुझे दिखाई दे रहा है। यह बात सही है कि आप इसको थोड़ा रेगुलेट कर पाएंगे। थोड़े समय के लिए आपको पता चल जाएगा कि कितने केवल आप्रेंटर्स इस देश में काम कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्रसारण हो रहा है इस देश में, मैं सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अपनी मां-बहन के साथ बैठ कर इन कार्यक्रमों को देख सकता है? मां-बहन की बात तो जाने दीजिए, अपनी पत्नी के साथ भी वह कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं। सरकार आज छोटे आप्रेंटर्स को इस बिल के माध्यम से रोकने के लिए, केवल आप्रेंटर्स को रोकने के लिए भी परेशान है। जो मंत्री जी यह बिल लाए हैं, वह इस का जवाब दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा बिल लाएं जिससे इस देश की संस्कृति, सभ्यता को बचाने

का काम करें। इसी उदारीकरण का नतीजा, फिलिपींस और थाईलैंड में जा कर आप देख सकते हैं फिलिपींस के प्रधान मंत्री को आज से कुछ दिन पहले कहना पड़ा कि इस उदारीकरण नीति का असर यह हुआ कि हमारा सारा देश वेस्पालय बन गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक राष्ट्र का प्रधान मंत्री कहता है कि इस उदारीकरण की नीति का उनकी संस्कृति पर यह असर हो रहा है। कहीं ऐसी नौबत यहां न आ जाए। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि विदेशी पैसे का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि भारत के प्रधान मंत्री यह कहने लगे कि इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, इस पैसे का पहला असर इसी विभाग पर होने वाला है। अखबार खोले जा रहे हैं, बड़े-बड़े लोग जिनके पास दौलत है, ताकत है, इस काम में आ रहे हैं जहां हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम किया जाएगा। मैं इस बिल का जहां एक ओर समर्थन करता हूं, वहां दूसरी ओर सिर्फ एक ही बात की गुजारिश करता हूं कि आप इस बिल के बारे में फिर से सोचिए और जल्द से जल्द, महीने दो महीने के अन्दर कोई ऐसा ताकतवर बिल लाइये जिससे यह लग सके कि भारत सरकार अपने सांस्कृतिक नियमों को संसादित करना चाहती है और सुचारूँ सांस्कृतिक नियम बना कर इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का प्रयास करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala) : Sir, I would like to make an important suggestion to the discussion going on, that is to solve the problem of the cultural invasion brought by our television system. I would like to call it peculiar kind of cultural slavery. Most of these TV programmes are leading our youth to a special type of cultural slavery which will be not in the interest of the country and the people. This is the basis of the problems

which have been highlighted by the Honourable Members who spoke here. Most of them were referring to the problem of the moral degradation contributed by our TV. In fact, that is a grave reality. My humble view is that this happens because of the absence of a correct concept of art. A living nation, must have a concept of art of its own. Then only will it be able to reform our cultural fields including our Television system at the national level. Nowadays what is going on ? If we have a look at it, if we are ready to make an inquiry into the police cases registered in the past, we will be able to find that the Chief villain behind most of the cases is our cinema and our TV programmes in which all the dangerous elements are being promoted and propagated. These people have no idea of art, they have no idea of morality, they have no idea of our most cherished spiritual values. Let us examine the case of the noon-shows and the midnight films that are shown on Doordarshan. They are nothing but the imitation of the western culture. It is okay that the western civilization has got its merits; there is no doubt about it. It has its spirit of inquiry. It has a central alertness. It respects freedom of expression and promotes harmony. But unfortunately in eastern countries like India, we are imitating the demerits of the western culture. I want to make one point clear, Sir, that these TV programmes shown nowadays are making our youth criminals. Mahatmaji's approach to art is not worthy in this regard. For him, art was life itself. I want to make a request to the hon. Minister : Kindly do the needful to arrange for the formulation of a correct concept of art for our television. At least form a body of experts for this purpose. Through art we must be able to see the realities of life, i.e. the aim of art must be to make life exuberant and powerful. One thing more, Sir, I want to

emphasise, that wine is promoted and woman is misused. In the T.V.'s programmes, woman's dignity is buried. She is depicted in a very bad manners. She is made an instrument for sexual anarchy. There are so many organisations in our country which are shedding tears for the cause of women, most of them are silent in this regard. It is a hard truth that woman is humiliated in the name of art. Here, I am reminded of a verse written by the great, renowned world poet and Philosopher Allama Iqbal :

“आह बेचारों के आसाब पर औरत  
है सवार” ।

That is the case of these so-called artists .

Therefore, my humble request is that all these problems the problem of liquor the wide publicity given to it through advertisements, and the humiliation of the woman-folk should be solved immediately and these tendencies are to be controlled strictly and provisions are to be made in the Bill to check this cultural degeneration and moral decay.

श्री शारदा महन्ती : (उड़ीसा) :  
उत्सवाध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत से बंध  
लोग इस बारे में बोल चुके हैं। मैं  
सिर्फ दो तीन बातें बोलूंगा। पहले तो  
जिस मंशा से मंत्री जी यह बिल ला  
हैं उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना  
है। मेरा यह पहला अनुरोध है। दूसरा  
यह है कि जो “जी” टी.वी. है या केबल  
टी.वी. है उसमें बहुत सी चीजें दिखाते  
हैं। बहुत अच्छे एपीसोड्स भी आ रहे  
हैं। मगर एपीसोड के लिये केवल पांच  
मिनट देते हैं और दस मिनट एडवर्टा-  
इजमेंट देते हैं। शराब का एडवर्टाइज-  
मेंट इतना ज्यादा होता है कि बोल नहीं  
सकते। एक मिनट के अन्दर एपीसोड  
दिखाते हैं फिर शराब का एडवर्टाइजमें  
“जी” टी.वी. “स्टार” टी.वी. या बी०  
बी०सी० ये सब जो बच्चा-बच्ची लोगों

[ श्री शारदा महन्ती ]

के पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम दिखाते हैं। वे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और टी.वी. देखने लगते हैं। हर घर में देखिये जहां "जी" टी.वी. है, स्टार टी.वी. है या दूसरा टी.वी. है ये सब देखते हैं। टी.वी. की मंशा क्या है? आम आदमी को सिखाने के लिये, समाचार देने के लिये टी.वी. है। मगर दूसरा सब दिखाते हैं। बच्चा लोगों की पढ़ाई तो खराब होती है... उन का चरित्र भी नष्ट हो जाता है और जो नंगा नाच दिखाते हैं वह भी चरित्र नष्ट करता है। कोई क्वेश्चन भी पुट करते हैं तो क्वेश्चन पुट करना अच्छा है, जो आम आदमी या सब आदमियों को जानना चाहिये।

यह जो शराब का एडवर्टाइजमेंट है, साबुन का एडवर्टाइजमेंट है या अन्य ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एपीसोड खत्म हो जाता है लेकिन उसका क्या अर्थ होता है वह हम लोगों को समझ में नहीं आता है। मंत्री जी, यह जो शराब का विज्ञापन है इसको बन्द करना बहुत जरूरी है। आप एपीसोड दिखाइये। एक और बात हम भूल रहे हैं मेट्रो चैनल में "श्रीकृष्ण" एपीसोड दिखा रहे हैं। आधे घंटे का टाइम है, मगर 20 मिनट का एडवर्टाइजमेंट और 10 मिनट का "श्रीकृष्ण" बीच में दिखाते हैं। यह सब बन्द करना चाहिये। श्रीकृष्ण दिखाना है, महाभारत दिखाना है, रामायण दिखाना है या दूसरे जो बड़े-बड़े मनीषी हैं उनकी कोई चीज दिखानी है, तो फुल टाइम दिखाइये। एडवर्टाइजमेंट मत दिखाइये। पैसों के लिये बच्चों का चरित्र नष्ट करना या अपने आदमियों का चरित्र नष्ट करना, यह ठीक नहीं है। विज्ञापन से वह पैसा कमाते हैं। मंत्री जी मेरी रेक्वेस्ट है कि यह सब बन्द करना चाहिये और इसकी जो मंशा है उसको पूरा करना है और उसका हम समर्थन करते हैं।

धन्यवाद।

SHRI S. S. SURJEWALA (Har-  
yana) : Mr. Vice-Chairman, I want to congratulate the young dynamic Minister for bringing in this legislation which is, in fact, very important. At the same time, I would like to say that the Bill, which has been introduced and is being discussed, is not a complete piece of legislation. Probably, it has been framed in a great hurry. I think in future a lot of gaps have to be filled up. There are a number of loopholes, for instance, the methodology for controlling the various programmes, which the cable TV operators are going to display or which they can display on their network, has not been provided in the Bill. The Minister or the Government may try to provide the same in the rules. Unless broad outlines are given in the Act itself, I don't think they will be able to control them or to make any specific provision through the rules for controlling them. Nobody can define what is to be permitted to be broadcast or displayed through the cables because the list will be very, very exhaustive. The broad outlines as to what negative is to be prevented or which cannot be displayed or allowed to be exhibited have not been given. It has only been mentioned about the advertisements that they are also likely to be controlled. But how the Government proposes to control them has not been mentioned. It is known to everybody that, with the economic liberalisation in the country, the floodgates have been opened for cultural invasion of the country through the media in general and the electronic media in particular. The economic liberalisation and other things are welcome because we cannot, as a nation, live in isolation. Various sections of the House have expressed their views about the programmes and the advertisements. The multinational companies and other commercial organisations in the country are giving

advertisements of all kinds of junk commodities and articles which are not desirable and which have led to a boom in consumerism in the country. And it has further led to great distortions economically and socially. Mr. Vice-Chairman, Sir, even sex is being used, rather mis-used very flagrantly. All kinds of advertisements of intoxicants, cigarettes, cloth and other consumer articles are being displayed with impunity. Probably one of the reasons is that our electronic media has not been able to create a network in the country, has not been able to prepare programmes which can fulfil the aspirations of the people of this country. There is a complete lack of technical and cultural institutions where people can be trained where writers can be encouraged and where folk programmes, folk-music, folk songs and folk stories can be prepared to fulfil the aspirations of the regional people. I would like to request the Minister that he should give greater emphasis on the programmes of regional culture and try to create a network in the country so that the people, instead of depending entirely on the cable television and foreign media, can depend more on the local media. Sir, there is always a tendency on the part of the administration to take advantage in the name of control or in the name of putting restrictions. There is all the likelihood that the local officers and local political bosses might try to give licences to those companies which are run by their own people and junior officers also can try to harass the people to distort money. The Cable Television Network means a lot of employment opportunities. But, no provision has been made about the selection. There is no mention in the Bill as to how many cable connections would be given to one town or one city and what criteria will be there to give

licences. There are many loopholes. I hope, the hon. Minister will try to fill up all the loopholes.

Thank you.

**SHRI VIREN J. SHAH :** Mr. Vice-Chairman, Sir, I am not rising to reply to the debate because the hon. Minister has yet to make his speech. I will speak two sentences for the hon. Minister's attention. Sir, while replying would the Minister be kind enough to give us the real reason for this Ordinance ? I must say with great respect that the explanatory statement which he has given is totally unconvincing. They have taken one and a half years. I would like to know why the Ministry could not move it during the last several Sessions. Is it something like the Prasar Bharati Act which was passed and which became law one and a half years ago and has not been implemented so far ? Is there something wrong with the functioning of the Ministry ? Sir, I will reply to the debate after the hon. Minister's speech.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) :** Mr. Viren Shah, as per the rule, if you want to move your Resolution now, then you are welcome.

**SHRI VIREN J. SHAH :** I think, as per the rule, it is only after the hon. Minister has replied to my points that I should move or withdraw my Resolution.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) :** You are required to speak before the Minister.

**SHRI VIREN J. SHAH :** Are you sure, Sir ? I had spoken on a number of Statutory Resolutions. The Minister has to reply to what I have said. Otherwise, how can I deal with it ? I have made my statement to begin with wherein I have brought out several points. So, unless the hon. Minister had dealt with them, how can I make my responding statement ? This is what has happened in the case of previous Ordinances too. This is not the first time that I have moved a Statutory Resolution. Anyway, I shall be obliged to know what the rule says in this regard.

**DR. BIPLAB DASGUPTA** (West Bengal) : There is one clarification which is very important. The amendment which has been proposed in clause 5 seems to be a sort of odd. Unless we know the purpose behind moving this amendment, it will be very difficult for us to make a decision on this. How can we respond unless we know the mind of the hon. Minister on this particular aspect as well ? I do not know what the formalities are. But our task will be made much simpler if the Minister would be kind enough to clarify one or two issues which were raised verbally or which have been moved in the form of amendments. Only then will it be easier for us to handle these issues and, perhaps, the hon. Member also can respond.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) :** The rule says : "The mover of a Resolution has the right of reply. But he has to protect his right by rising in his place and the Speaker does not undertake the responsibility of ascertaining in every case, before putting the question, whether the mover wishes to speak in reply. In case of Private Members' Resolution, the debate is treated as concluded after the Minister's speech if

the mover of the Resolution is not present to reply to the debate." Okay, Mr. Minister.

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) :** Mr. Chairman, Sir, my very good friend and a very old colleague of mine, Mr. Viren Shah, wanted me to give the real reason for issuing this Ordinance. The real reason is what I had stated. But since he is not convicted, I shall try my utmost to convince him because he is a very difficult person to convince. Sir, I will have to take a little of your time and I crave your indulgence. Sir, this Ordinance did not come all of a sudden nor has it been brought with any ulterior motive.

And, for this, I would like to go back to 1989. The advent of Cable TV Network in this country is attributed to No. 1, the high cost of the playback facility of the VCR and the VCP and No. 2, the availability at the turn of a switch of the additional software operation to the viewers of the kind never available to them in as dramatic a fashion as coverage of the Gulf War by the American Network, the CNN and the advent of telecast of the programmes of any foreign TV networks. I am deliberately not naming any of them for obvious reasons. The net result of this development was a haphazard mushrooming of cable TV networks in the country. Whether we admit it or not whether we like it or not, the fact is that it is what has happened. This unregulated growth prompted a detailed analysis of the issue and the possible ways to bring some discipline in this area. At present, the only provision relating to any regulation of TV networks

exists in the Indian Telegraph Rules 1951 under Rule 44.72 which states :

"Any person, may, without licence establish, maintain and work a telegraph, not being a wireless telegraph within the limits of a single building or estate.

provided that no telegraph line pertaining to the telegraph shall pass over or under a public road."

Accordingly, cables carrying TV signals which have to cross a public road require a licence from the Department of Telecommunications which is the telegraph authority in the country under the Indian Telegraph Act, 1935. Certain rules have been framed under the Act and some sections of the Act have been amended from time to time.

The then Minister of Information and Broadcasting appointed an Inter-Ministerial Committee in June, 1989 to study the various aspects of cable TV networks and dish antenna systems in the country and to make suitable recommendations. The Committee submitted its report in February, 1991. The matter was initially examined by the Department of Telecommunications as well as the Ministry of Information and Broadcasting. Thereafter, it was decided on 3-9-1992 in a Committee of Secretaries that the matter should be processed by the Ministry of Information and Broadcasting. The Inter-Ministerial Committee recommended that the cable TV networks should be permitted to operate within a carefully regulated framework. This was again examined by the Ministry of Information and Broadcasting and by a Committee of Secretaries and on 20th October, 1992, it was decided to set up an Inter-Ministerial Group once again under the chairmanship of the Additional Secretary, Department of Legal Affairs, to examine the necessity of enacting a law for the regulation of the

cable TV networks. The main intention was the regulation of TV networks because no Central law existed at that time. Till the ordinance was made, no Central law existed excepting the 1885 Telegraph Act. The Committee also decided that in view of the practical difficulties involved, there should be no licensing of TVRLs (?) as well as dish antennas except in specified areas such as those near the international borders. Then, the Group also made certain other recommendations. First is the mandatory licensing of cable TV networks for the time being. The second is, protecting the interests of consumers and this can be achieved by framing a separate skeletal law covering all aspects of law, i.e., hardware and software of the operations of the cable operators. The third is that the skeletal law should require the cable networks to conform to the provisions of the existing laws such as the Cinematograph Act, the Copyright Act, etc. In addition, advertisements on such networks should also conform to the various codes of advertising already in vogue. Monitoring of operations of cable TV networks would be done by the existing enforcement machinery without having to set up a separate infrastructure for this purpose. The fifth is that the technical performance specifications of cable TV networks at the head-end, trunk feeder system and the standardisation of cable equipment at the subscribers' end should be specified by the Bureau of Indian Standards.

Sixthly, punishment for violation of provisions of individual laws is to be under the respective Acts. In all other cases, the violation of the new could be made punishable with fine or with imprisonment up to five years or both.

This was again examined.....

5 P.M.

श्री संघ प्रिय गोतम (उत्तर प्रदेश) :  
वाईस-चेयरमैन साहब, आज हमारे एक  
साथी एम.पी. के बेटे की शादी है और  
उसमें हम सब लोग जा रहे हैं। कुछ  
बले गये हैं। यह विषय समाप्त होगा नहीं  
क्योंकि उन्हें बोलना है, इन्हें बोलना है  
इसलिये आप हाउस को एडजर्न कर दें  
और इसे कल ले लें। महोदय, पहले ही  
ढाई घंटे हो गये हैं जबकि 2 घंटे इसके  
लिये एलाट किये गये थे। ढाई बजे यह  
शुरू हुआ था तो साढ़े चार बजे समाप्त  
हो जाना चाहिये था। (व्यवधान) मगर  
अभी दो घंटे और लगेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश चव्वा) :  
मिनिस्टर को रिप्लाय करने दें फिर  
हाउस का अंतिम ले लेंगे।

SHRI K. P. SINGH DEO :  
committee of Secretaries again deli-  
berated on the 26th of November,  
1992.

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, I  
think the hon. Minister should take  
much longer time because he has to  
deal with many points. To rush him  
also would not be fair to the Bill or to  
my resolution condemning this. And  
I will also need at least 10 or 15  
minutes minimum, if not longer. That  
is why, if the House thinks it fit,  
we could adjourn the House just now..

SHRI K. P. SINGH DEO: I was  
going to respond to many of your  
points positively.

SHRI VIREN J. SHAH: That  
is why I said that since you will take

time, let us not rush you. We don't  
want to rush you. We want to hear  
you in great depth.

SHRI K. P. SINGH DEO: Would  
you be helpful in getting me to speak  
in the first hour tomorrow? Other-  
wise, again one day will be wasted.

...(Interruptions)...

Sir, I would like to abide by the  
wishes of the House in deference to  
the Members. But, then again sitting  
through the whole days means.  
(Interruptions) I have certain legisla-  
tion in the Lok Sabha also.

SHRI G. SWAMINATHAN: We  
can take it up tomorrow after the  
Zero Hour.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir,  
It should not be rushed. It is a very  
important Bill. Some of us have moved  
some important amendments and  
those amendments should not be  
dismissed or passed without a proper  
discussion. The Minister has made  
some points but he has a lot more  
points still to make. So, maybe to-  
morrow, after the Zero Hour...  
(Interruptions)

SHRI K. P. SINGH DEO: I  
would like to answer each and every  
point. I don't wish to run away.

...(Interruptions)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: So,  
if he can take it up at that time., I  
think that would be proper.

SHRI K. P. SINGH DEO: More-  
over, I would like to convince my  
good friend, Shri Viren J. Shah.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
SURESH PACHOURI): By the way  
how much time will you take for  
your reply?

SHRI K. P. SINGH DEO: Sir,  
at least half-an-hour. I would like to  
answer all the points. (*Interruptions*)  
Minimum half-an-hour, Sir. Many  
fundamental issues have been raised.  
(*Interruptions*)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :  
Sir, the House should be adjourned

because it will take one hour at the  
least. The Movers of the amendments  
also have to speak. You have taken  
the sense of the House. Now, you  
should adjourn it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
SURESH PACHOURI): What is the  
sense of the House? (*Interruptions*).

The House is adjourned till 11  
a.m. tomorrow.

The House then adjourned  
at four minutes past five of  
the clock till eleven of the  
clock on Tuesday, the 13th  
December, 1994.